



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2013/भाद्र 4, 1935

No. 189]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2013/BHADRA 4, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2013

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनगण. के मूल के या वहां से निर्यातित पैरासिटामोल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

फा. सं. 14/1009/2012-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए;

क मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित पैरासिटामोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में 30 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 60/1/2000-सी.शु. के तहत मूल पाटनरोधी जांच शुरू की थी। प्राधिकारी द्वारा 16 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और राजस्व विभाग द्वारा 6 सितंबर, 2001 की अधिसूचना सं. 89/2001-सी.शु. के तहत अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा 22 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं० 60/1/2000-डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा 27 मार्च, 2002 की अधिसूचना 29/2002-सी.शु. के तहत संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और यतः 23 जुलाई, 2007 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना के तहत प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी और उन्होंने संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की सिफारिश की थी। संबद्ध वस्तु पर 3 सितंबर, 2007 की सी.शु. अधिसूचना सं० 99/2007-सी०शु० के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अवधि में तदनुसार वृद्धि की गई थी।
3. यतः मै० श्री कृष्णा फार्मास्युटीकल लि०, हैदराबाद और भारत कैमिकल्स, मुंबई में अधिनियम और नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन संयुक्त रूप से दायर किया है जिसमें संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।
4. घरेलू उद्योग की ओर से दायर विधिवत पुष्टिकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए 28.8.2012 की अधिसूचना सं० 14/1009/2012-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केन्द्र सरकार द्वारा 19.9.2012 की अधिसूचना सं० 42/2012-सी.शु. (ए डी डी) के तहत 2 सितंबर, 2013 तक बढ़ा दी गई है। वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

**ख. प्रक्रिया**

5. संबद्ध जांच के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क. नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया गया था ।

ख. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को उपलब्ध कराई । अगोपनीय रूपांतरण की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी जिसे अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था ।

ग. प्राधिकारी ने नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चीन, जन.गण. में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को घरेलू उद्योग ने उपलब्ध कराए थे) को निम्नानुसार भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया :

- i. अनहुई बायी कैमिकल इंड. कंपनी लि०
- ii. झेजियांग कांगले फार्मा कंपनी लि०
- iii. वेंझोऊ फार्मा फैक्ट्री
- iv. चांगशू हुआगांग फार्मा कंपनी लि०
- v. हेबाई जिहेंग ग्रुप कंपनी लि०
- vi. हेबाई जिहेंग (ग्रुप) फार्मसी कंपनी लि०
- vii. हुआऊ वीगांग इंटरप्राइजेज ग्रुप कार्पो०
- viii. झोगजिन फार्मा तियानजिन जिनजिन फार्मास्युटीकल
- ix. जियागशू ग्वाटाल इंटरनेशनल ग्रुप कंपनी लि०
- x. लाओयुआन सिटी बैकांग फार्मास्युटीकल
- xi. शंघाई बेलियन कैमिकल्स कंपनी लि०

घ. बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार (एम ई टी) संबंधी प्रश्नावली चीन जन.गण. के सभी ज्ञात निर्यातकों और दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराएं। हालांकि जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य पर भारत में विधिवत समायोजित संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर विचार किया गया था, तथापि, प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों को यह सूचना दी थी कि उसका प्रस्ताव यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के मददेनजर आवेदक के दावे की जांच करने का है। अतः चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों से अनुरोध किया गया था कि वे पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेखानुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकें कि क्या सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जा सकता है।

ड. निर्धारित समय सीमा के भीतर संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। मै0 हेबाई जीहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कंपनी लि0 द्वारा अत्यधिक विलंब से निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया था जिसे प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किया था। तथापि, चीन की उपर्युक्त कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।

च. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित सभी ज्ञात आयातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे), को भेजी और नियम 6(4) के अनुसार, उन्हें पत्र जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी :

- i. अजंता फार्मा लि0
- ii. सिपला लि0
- iii. सिरोन दुर्ग फार्मास्युटीकल्स लि0
- iv. फ्लेमिंगो फार्मास्युटीकल्स लि0
- v. इंडोबो रेमीडीटीज लि0
- vi. मनीष फार्मास्युटीकल्स प्रा0 लि0
- vii. मंगलम दुर्ग एंड ऑर्गेनेक्स लि0

viii. मेडोफार्म

ix. टेक्नो इकॉनोमिक्स सर्विसेज प्रा० लि०

x. हेल्दी लाइफ फार्मा प्रा० लि०

xi. ग्लो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग प्रा० लि०

xii. आई पी सी ए लैब्स

xiii. ट्राइटन लेबोरेटरियल लि०

xiv. वामसी लैब्स लि०

xv. श्रीनिवास एग्रो इंड. एंड ड्रग्स लि०

छ. आवेदकों के अलावा प्राधिकारी ने आवेदन में प्रदान की गई सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों को भी जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति निम्नानुसार उपलब्ध कराई :

i. पारा प्रोडक्ट्स

ii. सारा एक्सपोर्ट्स लि०

iii. पान ड्रग्स लि०

iv. पैरामाउंट हेल्थ केयर लि०

v. फार्मसन एनालजेसिक्स

vi. अल्फा ड्रग्स लि०

vii. ग्रेन्यूल्स इंडिया लि०

ज. नियम 6(7) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जिसे उनके निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

झ. जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रदान की है अथवा इस जांच में अत्यधिक बाधा

- हाली है, प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर ये विवरण दर्ज किए हैं और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है ।
- ट. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वे जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करें ।
- ठ. भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए आवेदकों से सूचना मांगी गई थी ।
- ड. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है ।
- ढ. हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी ने 11 जून, 2013 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की । सुनवाई के समय जो हितबद्ध पक्षकार उपस्थित हुए थे, उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी और उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों के उत्तर दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया था ।
- ण. जांच की कार्यवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी ने संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया है ।
- त. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर स्थापन किया गया था ।
- थ. प्राधिकारी द्वारा ये जांचें 1 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012 (15 माह) की जांच अवधि के लिए की गई हैं । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 08—मार्च, 09, अप्रैल 09—मार्च, 10, अप्रैल, 10—मार्च, 11 की अवधि और जांच अवधि शामिल थी ।
- द. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा जांच के आवश्यक तथ्यों का प्रकटन 19 अगस्त, 2013 के पत्र के तहत ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया है ।
- ध. \*\*\* यह चिन्ह इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

न. प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के लिए विनिमय दर 47.66 रुपए = 1 अम.डा. के रुप में ली गई है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और समान वस्तु

6. मूल और प्रथम एसएसआर जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का या वहां से निर्यातित "पैरासिटामोल जिसे ऐसीटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है" है । वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण इस जांच में मूल जांच और प्रथम एस एस आर जांच में शामिल उत्पाद शामिल हैं ।
7. पैरासिटामोल एक गंधहीन सफेद खट्टा पाउडर होता है । इसका रासायनिक सूत्र  $C_8H_9NO_2$  है । पैरासिटामोल एक बल्क भेषजीय सक्रिय संघटक है, जिसमें पीड़ानाशक और ज्वरांतक गुणधर्म होते हैं । इसका उपयोग पाउडर, ग्रेन्यूलों, इंजेक्टीबल और टेब्लेटों के रूप में कई आर एक्स और ओ टी सी औषध के नुस्खों में होता है । पैरासिटामोल एक कार्बनिक रसायन है और यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सी.शु. उपशीर्ष 2922.2933 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।
8. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण और प्राधिकारी द्वारा पूर्व में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू होने की वजह से प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो कि पूर्ववर्ती जांचों में है । इसके अलावा, किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

घरेलू उद्योग के अनुरोध

9. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:—
  - i. श्री कृष्ण फार्मास्यूटीकल लि०, हैदराबाद और भारत कैमिकल्स, मुंबई में याचिका दायर की है और मै० सारा एक्सपोर्ट्स, मै० पारा प्रोडक्ट्स, मै० फार्मसन एनालजेसिक्स तथा मेघमणि यूनिकैम ने आवेदन का समर्थन किया है ।
  - ii. ऐसी कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है कि जिन कंपनियों ने मूल जांच के समय भागीदारी की थी, उन्हें वर्तमान जांच में भाग लेना चाहिए । याचिकाकर्ता पर उन घरेलू

- उत्पादकों की भागीदारी मांगने के संबंध में कोई दायित्व नहीं है, जिन्होंने मूल जांच के समय भागीदारी की थी । अन्य घरेलू उत्पादकों की भागीदारी न होने के कारण याचिकाकर्ता के अधिकार कम नहीं हो सकते ।
- iii. याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है, और इसलिए वह वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार की मांग करने का हकदार है ।
- iv. नियमानुसार, एकमात्र अपेक्षा यह है कि भागीदार कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए । उत्पादन के बड़े हिस्से का तात्पर्य 50 प्रतिशत से अधिक से नहीं है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती मामलों अर्थात् जिंग ऑक्साइड में ऐसे घरेलू उद्योग के लिए सूचना के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं जिनकी कंपनियों का सामूहिक उत्पादन 50 प्रतिशत से कम था ।
- v. याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता कंपनियों के बारे में सूचना प्रदान की है । जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने उनके पास यथोचित रूप से उपलब्ध सूचना प्रदान की है । निर्यातकों द्वारा नामजद अन्य कंपनियों के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई सूचना नहीं है ।
- vi. जांच की शुरुआत के बाद मै0 फार्मसंस एनालजेसिक्स ने वर्तमान जांचों से संगत लागत निर्धारण और क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है । उक्त सूचना 9 जुलाई, 2013 के पत्र के तहत दायर की गई है ।
- vii. ग्रेनूल्स इंडिया लि0 एक 100 प्रतिशत ई ओ यू है और वह घरेलू बाजार में कोई खास बिक्री नहीं करती है ।
- viii. अल्फा ड्रग्स इंडिया लि0 का आमेलन पंजाब कैमिकल्स तथा क्रॉप प्रोटेक्शन लि0 (पी सी पी एल) में हो गया है और ये पेरसिटामोल के उत्पादक नहीं हैं ।
- ix. पान ड्रग्स लि0 और पेरामाउंट हेल्थ केयर लि0 पेरसिटामोलिन का उत्पादन नहीं करते हैं और घरेलू बाजार में उसकी आपूर्ति नहीं करते हैं ।
- x. भारत के मूल के या वहां से निर्यातित ऐसीटामिनोफेन पर पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा के मामले में दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम 17.2. 2007 को जारी किए गए थे । पाटन हेतु जांच की अवधि 1 जुलाई, 2004 से 30 जून, 2005 की थी और क्षति जांच में 1 जुलाई, 2002 से 30 जून, 2005 तक की अवधि के आंकड़ों का मूल्यांकन शामिल था । यह नोट करना संगत है कि उक्त



जांच परिणाम भारतीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई प्रथम निर्णायक समीक्षा से भी पहले जारी किया गया था । भारतीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 23.7.2007 की अधिसूचना के तहत प्रथम निर्णायक समीक्षा जांच परिणाम जारी किए थे ।

- xi. दक्षिण अफ्रीकी जांच परिणाम में नामजद पेरासिटामोल की 37 कंपनियों के संबंध में दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि श्रीकृष्णा फार्मास्युटल लि० को छोड़कर किसी अन्य कंपनी ने तो स्वयं को अभिज्ञात किया है और न ही दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारी को कोई उत्तर दिया है । दक्षिणी अफ्रीकी प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम यह निर्णय करने के लिए निर्णायक साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि क्या वर्तमान जांच में वे संबद्ध वस्तु के उत्पादक हैं ।
- xii. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि निम्नलिखित उत्पादकों के बारे में सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है और ये कंपनियां दक्षिण अफ्रीका के जांच परिणाम में नामजद है।
- i. अल्फा रेमेडीज लि०
  - ii. डायनस फार्मास्युटिकल्स
  - iii. जी.एम्ब्रे लेबोरेटरी
  - iv. जामहिक डाईकैम इंडस्ट्रीज
  - v. ट्रायोकैम प्रोडक्ट्स लि०
  - vi. जूम आर्गेनिक लि०

यह अनुरोध किया गया है कि उपर्युक्त में से कोई भी पक्षकार संबद्ध वस्तु का उत्पादक नहीं है । वे अधिकांशतः केवल पेरासिटामोल की गोलियों का निर्माण करते हैं जो वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तु नहीं है ।

- xiii. जहां तक आगे किए गए इस दावे का संबंध है कि मेघमणि यूनीकैम भी संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है जिसकी क्षमता बैव सूचना के अनुसार 7500 मी०ट० प्रति वर्ष है । मेघमणि यूनीकैम लि० वर्ष 2011 में स्थापित एक ऐसीजैट इकाई है । यह अनुरोध किया जाता है कि इस आशय की कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है कि मेघमणि यूनीकैम ने अपने वाणिज्यिक उत्पादक कब शुरू किया, क्या उन्होंने एसीजैट इकाई होने के नाते घरेलू बाजार में किसी मात्रा की बिक्री की है ।

- xiv. इसके अलावा, 7.3.2012 की वैब सूचना के अनुसार गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जी पी सी बी) के अधिकारियों ने जी आई डी सी पाइप लाइन में शोधन किए बिना सीधे खतरनाक निस्सारण डालने के लिए मेघमणि यूनीकैम लि० के दहेज संयंत्र को तुरंत बंद करने के लिए नोटिस जारी किया है ।
- xv. यह अनुरोध किया जाता है कि किसी निर्णायक साक्ष्य के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि मेघमणि यूनीकैम संबद्ध वस्तु का उत्पादक है जो संगत अवधि में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री कर रहा है और उनके आरोपित उत्पादन को याचिका के आधार का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ पात्र घरेलू उत्पादन माना जा सकता है ।
- xvi. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल बल्क औषधि है और इसमें नुस्खे शामिल नहीं हैं । इसके अलावा वर्तमान जांच की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है । मेघमणि आर्गेनिक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना का कभी कोई उत्तर नहीं दिया है । कंपनी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि वे संबद्ध वस्तु के घरेलू विनिर्माता भी हैं और उन्होंने जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन किया है ।
- xvii. इस बात के होते हुए भी यदि मेघमणि आर्गेनिक्स के उत्पादन पर किए गए दावे की सीमा तक विचार किया जाता है तो यह नोट किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 39 प्रतिशत बनेगा और समर्थकों के साथ याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 74 प्रतिशत बनेगा ।
- xviii. याचिकाकर्ता कंपनी की एक संबद्ध इकाई, मै० श्रीकृष्णा फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा आयात किए गए थे और ये आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए गए हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना है कि अग्रिम लाइसेंस पर किए गए आयातों से कोई कंपनी घरेलू उद्योग माने जाने से वंचित नहीं हो जाती है ।
- xix. किसी निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योग का आधार और क्षेत्र प्रासंगिक नहीं होते हैं ।
- xx. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन न केवल आधार संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है अपितु वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग भी है ।

#### अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

10. मै० हेबाई जीहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कंपनी लि० द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. जिन उत्पादकों ने आरंभिक जांच के दौरान घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने वर्तमान याचिका में भाग नहीं लिया है। इस आशय का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है और न ही कारण दिया गया है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने पूर्ववर्ती जांचों में उत्पादक थे, उन्होंने वर्तमान जांच में भाग क्यों नहीं लिया है।
- ii. याचिकाकर्ताओं ने अन्य प्रमुख घरेलू उत्पादकों अर्थात् ग्रेन्यूल इंडिया लि०, अल्फा ड्रग्स इंडिया लि०, पान ड्रग्स इंडिया लि०, पैरामाउंट हेल्थ केयर लि० और फार्मसंस एनालजेसिक्स के उत्पादन ब्यौरे शामिल नहीं किए हैं।
- iii. भारत में संबद्ध वस्तु का कुल उत्पादन 47651 मी०ट० है न कि 21401 मी०ट०, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। भारत में वास्तविक कुल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा केवल 23.51 प्रतिशत बनता है।?
- iv. दो बड़े उत्पादकों (ग्रेन्यूलस इंडिया और फार्मसंस एनालजेसिक्स) को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है।
- v. श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल्स की एक संबद्ध इकाई ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग का भाग नहीं बन सकती।
- vi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1 ख) के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच में घरेलू उद्योग का आधार एक अनिवार्य मानदंड होता है।
- vii. दक्षिण अफ्रीकी जांच परिणाम के अनुसार भारत में पैरासिटामोल के 37 उत्पादक हैं। वर्तमान याचिका में ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।
- viii. अल्फा रेमेडीज लि०, दिनेश फार्मास्युटीकल, जी.एम्फे लेबोरेटरीज, जामहिक डाइकैम इंडस्ट्रीज, ट्राईकैम प्रोडक्ट्स लि०, जूम आर्गेनिक लि० और मेघमणि यूनीकैम द्वारा पैरासिटामोल के उत्पादन के ब्यौरे जैसे कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास आधार का अभाव है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षति की संभावना दोषपूर्ण है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

11. श्री कृष्णा फार्मास्युटीकल लि०, हैदराबाद और भारत कैमिकल्स, मुंबई ने यह याचिका दायर की है। बाद में मै० सारा एक्सपोर्ट्स लि०, मै० पारा प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, मै० फार्मसन

एनालजेसिक्स (फार्मसन फार्मास्युटीकल गुजरात प्रा० लि० की एक इकाई) और मै० मेघमणि यूनीकैम एल एल पी ने याचिका का समर्थन किया है । घरेलू उद्योग के आधार के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर नीचे विचार किया गया है ।

12. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जिन उत्पादकों ने आरंभिक जांच के दौरान घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके तहत ऐसे उद्योगों को प्राधिकारी के समक्ष आना आवश्यक हो ।
13. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि अन्य प्रमुख घरेलू उत्पादकों अर्थात् ग्रेन्युल इंडिया लि०, अल्फा ड्रग्स इंडिया लि०, पान ड्रग्स इंडिया लि०, पेरामाउंट हेल्थ केयर लि० और फार्मसंस एनालजेसिक ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा में भाग नहीं लिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना उक्त उद्योगों को इस अनुरोध के साथ उपलब्ध कराई गई थी कि वे संगत सूचना उपलब्ध कराएं । परंतु उक्त उद्योगों ने उत्तर नहीं दिया । तथापि, बाद में मै० फार्मसंस एनालजेसिक ने लागत निर्धारण और क्षति संबंधी सूचना प्रदान की । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार ग्रेन्युल्स इंडिया लि० एक 100 प्रतिशत पी ओ यू है और वह घरेलू बाजार में कोई खास बिक्री नहीं करती है । इसके अलावा, प्रथम निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का आयातक होने के कारण मै० ग्रेन्युल्स इंडिया लि० को बाहर रखा था ।
14. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि भारत में संबद्ध वस्तु का कुल उत्पादन 47651 मी०ट० है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा दावा अपुष्टिकृत है । इसके अलावा, उपर्युक्त अन्य घरेलू उत्पादक, जिनसे जांच की शुरुआत के बाद संगत सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, प्राधिकारी के समक्ष नहीं आए हैं ।
15. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल्स की एक संबद्ध इकाई ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग का भाग नहीं बन सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी किसी स्थिति से कोई घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने से स्वतः अयोग्य हो जाता है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि संबंधित घरेलू उत्पादक संबद्ध देश द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन का एक लाभानुभोगी है । वर्तमान मामले में श्री कृष्णा फार्मास्युटीकल्स के संबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए आयात इस तथ्य की स्वीकारोक्ति है और यह बताया गया है कि उसने जांच अवधि के दौरान शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत केवल 238 मी०ट० पेरसिटामोल का आयात किया है । शुल्क छूट के अंतर्गत किए गए शुल्कमुक्त आयात निर्यात प्रयोजन हेतु

वस्तु के विनिर्माण के लिए होते हैं और ऐसे शुल्क मुक्त आयातों का व्यापार घरेलू बाजार में नहीं किया जा सकता ।

16. संबद्ध वस्तु के बारे में दक्षिण अफ्रीका के किस जांच परिणाम पर विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने भरोसा किया है, वह वर्ष 2007 से संबंधित है । उक्त जांच परिणाम में किसी साक्ष्य के बिना 37 भारतीय उत्पादकों को मात्र अभिज्ञात किया गया था, इसके अलावा, श्रीकृष्णा फार्मास्यूटीकल्स लि०, जो वर्तमान निर्णायक समीक्षा में एक याचिकाकर्ता है, एकमात्र ऐसा भारतीय उत्पादक था, जिसने दक्षिण अफ्रीकी जांच में भाग लिया था । इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस दावे को न्यायोचित ठहराने के लिए स्वयं कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि वे घरेलू बाजार में उत्पादन और बिक्री में शामिल भारत में संबद्ध वस्तु के कुल 37 उत्पादक हैं ।
17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा में यह आवेदन मै० श्रीकृष्णा फार्मास्यूटीकल्स लि० और मै० भारत कैमिकल्स द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है । मै० सारा एक्सपोर्ट्स और मै० परा प्रोडक्ट्स और मै० मेघमणि यूनिकैम एल एल पी ने आवेदन का समर्थन किया है । संबद्ध वस्तु के एक अन्य घरेलू उत्पादक अर्थात् मै० थानसन एनालजेसिक ने भी, जो प्रथम निर्णायक समीक्षा में घरेलू उद्योगों के एक संघटक था, ने आवेदन का समर्थन किया है और लागत तथा क्षति सूचना प्रदान की है । शेष अन्य उत्पादक, यदि कोई हो, ने सूचना प्रदान करने के प्राधिकारी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया । इसके अलावा, वर्तमान जांच का विरोध करने वाला इस उत्पाद का कोई भी घरेलू उत्पादक नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पात्र भारतीय उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

विवरण	यू ओ एम	जांच अवधि		याचिका के अनुसार	
		उत्पादन	हिस्सा	उत्पादन	हिस्सा
याचिकाकर्ता	मी०ट०	11,201	47.34	8,779	46.26
भारत कैमिकल्स	मी०ट०	***	***	***	***
श्री कृष्णा फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	मी०ट०	***	***	***	***
आवेदन का समर्थन करने वाले अन्य उत्पादक	मी०ट०	12,459	52.66	10,200	53.74
फार्मसन एनलजेस्टिक्स	मी०ट०	***	***	***	***
परा प्रोडक्ट्स प्रा० लि०	मी०ट०	***	***	***	***
सारा एक्सपोर्ट लि०	मी०ट०	***	***	***	***
मेघमणि यूनिकैम एलएलपी	मी०ट०	***	***	***	***
कुल भारतीय उत्पादक	मी०ट०	23,660	100.00	18,979	100.00

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और नियमों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि मै० श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल्स लि० और मै० भारत कैमिकल्स का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए घरेलू उद्योग है ।

### ड. विविध मुद्दे

#### घरेलू उद्योग के अनुरोध

18. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :—

- i. प्राधिकारी ने मै० हेबाई जीहैंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कंपनी लि० द्वारा विलंब से दायर किए गए उत्तर को सही तरीके से अस्वीकृत किया है ।
- ii. उपर्युक्त कारण को ध्यान में रखते हुए मौखिक सुनवाई के समय उपस्थित निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार/मान्य नहीं किया जाना चाहिए ।
- iii. अमरीका—अर्जेन्टीना से ओ सी टी जी पर पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा के मामले में डब्ल्यू टी ओ के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 6.1 और 6.2 के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकारों के लिए “अनिश्चित” अधिकारों का प्रावधान नहीं है ताकि प्रतिवादी अपने विकल्प के अनुसार संगत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें, सुनवाई में भाग ले सकें अथवा क्षति में भागीदारी कर सकें ।

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :—

- i. मै० हेबाई जीहैंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कंपनी लि० द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार किया जाना चाहिए था क्योंकि वे जांच में भाग लेने वाले एकमात्र निर्यातक हैं ।
- ii. भारतीय पाटनरोधी कानून में ऐसी कोई वास्तविक सांविधिक समय—सीमा नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमाओं के बाद उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता ।
- iii. याचिकाकर्ता द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने 4 अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन, आयात मात्रा और उसके विश्लेषण, वार्षिक लेखों आदि जैसी काफी सूचना का खुलासा नहीं किया है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 हेबाई जीहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल् कंपनी लिमिटेड ने अत्यंत विलंबित चरण पर उत्तर दायर किया और ऐसे विलंबित उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए कोई उचित और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह नोट किया जाता है कि किसी जांच में भागीदारी के अधिकार को असीमित नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी के लिए उत्तर में विलंब करने हेतु दिए जाने वाले न्यायोचित कारणों के बिना भी विलंब को माफ करना अपेक्षित नहीं है।

21. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।

जहां तक सूचना की गोपनीयता का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार उपबंध है —

(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी नियम (5) के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियों अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त किसी अन्य सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने के बाद उसके द्वारा गोपनीय माना जाएगा और ऐसी किसी सूचना का प्रकटन ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को नहीं किया जाएगा। (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदाता पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है तो ऐसा पक्षकार ऐसे कारणों का एक विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है या सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत रूप में या सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

22. अंतिम जांच परिणाम देने से पूर्व आवश्यक तथ्यों के प्रकटन का उपबंध पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में निर्धारित किया गया है। नियम 16 में भी गोपनीय तथ्यों का प्रकटन "संबंधित हितबद्ध पक्षकारों" को ही किए जाने की अपेक्षा की गई है जबकि अगोपनीय तथ्यों

का प्रकटन सभी हितबद्ध पक्षकारों को किया जाना अपेक्षित है । किसी भी चरण पर प्राधिकारी को प्रतिस्पर्धी और विरोधी हित रखने वाले पक्षकारों को गोपनीय सूचना का प्रकटन करने की शक्ति नहीं दी गई है ।

23. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की समेकित सूचना को गोपनीय रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि किसी समेकित आंकड़े का प्रकटन किया जाता है तो उससे हितबद्ध पक्षकार गोपनीय संघटक आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए उनका प्रकटन हितबद्ध पक्षकारों के सर्वोत्तम हित में नहीं किया जा सकता ।

24. जहां तक प्रारंभिक जांच परिणाम के चरण पर पाटन मार्जिन की गणना का प्रकटन न किए जाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन के चरण पर ही ऐसी सूचना का प्रकटन किया जाता है ।

#### च. पाटन मार्जिन, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की गणना

25. प्राधिकारी ने निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से सूचना प्रदान करने की सलाह देते हुए संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं । चीन जन.गण. के मै0 हेबाई जीहेंग (गुप) फार्मास्युटीकल कंपनी लि0 द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर, जिसे विलंबित चरण पर प्रस्तुत किए जाने के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है, को छोड़कर किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग नहीं किया है ।

#### घरेलू उद्योग के अनुरोध

26. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि :

- i. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों में से एक शेयरधारक राज्य की स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है निर्दिष्ट प्राधिकारी और यूरोपीय आयोग ने निरंतर यह माना है कि ऐसे मामलों में राज्य के हस्तक्षेप की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता । यह माना गया है कि यह न केवल विगत हस्तक्षेपों का प्रश्न है अपितु बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने के लिए संगत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भविष्य में राज्य के हस्तक्षेप की संभावना का भी प्रश्न है ।



- ii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतों में बाजार मूल्यों का पर्याप्त प्रदर्शन होता है— “बाजार मूल्यों के पर्याप्त प्रदर्शन” की व्यापक व्याख्या की गई है ताकि यह अर्थ निकाला जा सके कि इन निविष्टियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होनी चाहिए । यह तथ्य नितांत अपर्याप्त है कि ऐसी कीमतें चीन जन.गण. में प्रचलित कीमत से तुलनीय हैं ।
- iii. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं करता है कि उनकी बहियों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुरूप की जाती है— ऐसी स्थितियों में बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार को खारिज किया जाना चाहिए जिनमें चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं कि उनकी बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों (आई ए एस) के अनुरूप हैं । अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों के अनुपालन पर जोर देने की जरूरत वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित राजस्व एवं व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं की सत्यता और यथातथ्यता सुनिश्चित करने के लिए है ।
- iv. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा उस स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता यदि एक भी मापदंड की पूर्ति होती है : बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के निर्धारित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच पर खरे नहीं उतरते हैं । यह स्थिति वास्तविक क्षति के लिए अपक्षित जांच के ठीक विपरीत है । यह एक विधिवत स्वीकार की गई स्थिति है कि क्षति का सकारात्मक जांच परिणाम उस स्थिति में भी दर्ज किया जा सकता है जब एक ही मापदंड से क्षति की पुष्टि होती हो । इस प्रकार जहां क्षति की मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए एक मापदंड पर्याप्त है, वहीं बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को रद्द करने के लिए एक ही मापदंड पर खरे उतरने में विफलता पर्याप्त है ।
- v. सिद्ध करने का भार/दायित्व — यह सिद्ध करने का दायित्व प्राधिकारी पर नहीं है कि चीन की कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के वातावरण में प्रचालन कर रही हैं और वह बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की हकदार हैं । इसके विपरीत यह सिद्ध करना चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का दायित्व है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रही हैं ।

**vi.** समग्र रूप में समूह का उत्तर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप में इसका दावा नहीं करते हैं । यदि उक्त समूह के भागस्वरूप एक या अधिक कंपनियों ने उत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को अस्वीकृत किया जाना चाहिए

**vii.** रूपांतरण :ऐसी स्थिति जिसमें वर्तमान शेयरधारकों ने स्वयं उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, परंतु किसी अन्य पक्षकार ने इन्हें अर्जित किया है, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि रूपांतरण की प्रक्रिया की पूर्णतः पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए नहीं की जाती है ।

27. अमरीका एक विकसित देश है जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि अमरीका को एक प्रतिनिधिक देश के रूप में नहीं माना जा सकता । यूरोपीय आयोग ने कई मामलों में अमरीका को प्रतिनिधिक देश माना है ।

उत्पादक/निर्यातक/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

28. सामान्य मूल्य की गणना के लिए अमरीका पर प्रतिनिधिक देश के रूप में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक विकसित देश है ।

प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत और डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्यातक देश अथवा अलग-अलग निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा उक्त अनुमान के खंडन के अधीन है ।

30. पाटनरोधी नियमावली के पैरा-8, अनुबंध-1 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन का निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके प्रतिकूल सिद्ध करता है । चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन.जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;
- इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जांच शुरूआत संबंधी सूचना जारी किए जाने के बाद चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के खंडन की मांग नहीं की है। चूंकि चीन की किसी भी कंपनी ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का निर्धारण नहीं किया है कि क्या चीन के किसी उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जा सकता है ।

#### चीन के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

32. घरेलू उद्योग ने चीन में सामान्य मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ उचित प्रतिनिधिक देश के रूप में अमरीका का विरोध किया और उसने जांच अवधि के दौरान अमरीका में संबद्ध वस्तु की कीमत के बारे में कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए । बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से कीमत के विकल्प के रूप में घरेलू उद्योग ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए भारत में देय कीमत के रूप में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।
33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करते समय बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के

विकास के स्तर पर विधिवत विचार किया जाना चाहिए । चीन जन.गण. और अमरीका के बीच आर्थिक विकास के अलग-अलग स्तरों और संबद्ध वस्तु के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में अमरीका में विचार नहीं किया है और उन्होंने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है ।

34. चूंकि चीन के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है ।

35. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उपबंध है कि :

“गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी। ”

36. वर्तमान जांच में संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और उत्तर दायर नहीं किया है । इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने नियमों में यथा परिभाषित कोई अन्य वैकल्पिक आधार प्रदान नहीं किया है जिसके अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सके । उपर्युक्त स्थिति पर विचार करते हुए और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन को मानते हुए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में यथा निर्धारित अन्य तरीकों के बारे में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने “अन्य उचित आधार” का तरीका अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । अतः प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य व प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर और प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय

कीमत पर विचार करते हुए चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । तदनुसार, चीन के निर्यातकों के लिए परिकलित सामान्य मूल्य \*\*\* अम. डा. प्रति किग्रा. निर्धारित किया जाता है ।

### निर्यात कीमत

37. चूंकि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है । इस प्रयोजनार्थ डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार आयात मात्रा पर भरोसा किया गया है । सी आई एफ कीमत में समायोजन रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किए गए हैं । तदनुसार, निर्यात कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों, कमीशन, चीन में पत्तन व्यय और अंतरदेशीय भाड़े का समायोजन किया गया है । उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर भारत के लिए चीन.जन.गण. से निर्यातों की निवल कारखाना निर्यात कीमत \*\*\* अम. डा. प्रति किग्रा. निर्धारित की जाती है ।

### पाटन मार्जिन का निर्धारण—जांच अवधि

38. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और कारखाना स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना करते हुए संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

विवरण	अम.डा. /किग्रा.	रू./किग्रा.
सामान्य मूल्य	***	***
निर्यात कीमत	***	***
पाटन मार्जिन	***	***
पाटन मार्जिन %	***	***
रेंज %	20-30	20-30

### छ. क्षति निर्धारण की कार्य प्रणाली और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच :

#### घरेलू उद्योग के अनुरोध

39. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(क) चीन से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन हो रहा है ;

- (ख) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन में तेजी आने की संभावना है;
- (ग) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयात की मात्रा काफी अधिक है ।
- (घ) कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक है !
- (ङ) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार नहीं हुआ है । इस प्रकार वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत पर बिक्री करने का विकल्प चुनता है तो घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटा होगा ।
- (च) बिक्री लागत में जांच अवधि में वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री कीमत में गिरावट आई है ।
- (छ) संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के कारण घरेलू उद्योग ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया । तथापि, क्षमता उपयोग में गिरावट आई है ।
- (ज) कुछ स्तर प्राप्त करने के बाद जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट प्रदर्शित होती है । जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है ।
- (झ) लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में वर्ष 2009-10 तक सुधार हुआ और उसके बाद गिरावट शुरू हो गई जो जांच अवधि में आगे और घटकर नकारात्मक स्तर पर पहुंच गई ।
- (ट) मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई ।
- (ठ) मांग में आए परिवर्तनों की तुलना करने पर उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई ।
- (ड) वर्तमान जांच अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद इसमें सुधार आना चाहिए था ।
- (ढ) घरेलू उद्योग पाटन के पिछले दुष्प्रभावों से अभी उबरा नहीं है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से भविष्य में घरेलू उद्योग को और अधिका क्षति पहुंचेगी ।

- (ण) बढ़ती हुई मांग और घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही इतनी कम कीमत के बावजूद मालसूची का स्तर काफी अधिक है । देश में मांग के अनुपात में बिक्री मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है जबकि घरेलू उद्योग को मांग में वृद्धि की दर से आगे अपनी बिक्री को बढ़ाने की उम्मीद थी ।

उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

40. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं :-

- (क) क्षति का निर्धारण भ्रामक है क्योंकि यह दो छोटे उत्पादकों के आधार पर किया गया है ।
- (ख) जांच अवधि के दौरान अधिकांश आयात शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए हैं । शुल्क मुक्त आयातों का घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ।

जांच अवधि के दौरान अधिकांश आयात शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत किए गए हैं । शुल्क मुक्त आयातों का घरेलू बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसलिए पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

41. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रयाप्त स्तर तक बढ़ गई होती । "
42. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे घरेलू उद्योग की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया गया है ।

43. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में यह उपबंध है कि नियम 11 के उपबंध समीक्षा के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। अतः प्राधिकारी ने अनुबंध-11 के साथ पठित आवश्यक परिवर्तनों के साथ नियम 11 के उपबंधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जनगण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के तथ्य पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करते समय ध्यान देना अपेक्षित है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए मौजूदा उपाय पर्याप्त है अथवा नहीं।
44. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के अधिकांश आयात शुल्क मुक्त स्कीमों के अंतर्गत हुए हैं। तथापि, उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने दावे की पुष्टि नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित क्षति विश्लेषण से घरेलू उद्योग की स्थिति तथा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा हुई क्षति का पता चलता है।

#### पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव:

#### आयात मात्रा और बाजार हिस्सा :

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

45. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पहले समाप्त न किया गया हो, तो वह इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा। परंतु यदि केन्द्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत हो कि ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर शुल्क को इस प्रकार से लगाए जाने की अवधि को आगे और 5 वर्ष तक बढ़ा सकती है और बढ़ाई गई इस प्रकार की अवधि ऐसे समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
46. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध-11 में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि क्या



पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती ।

47. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है : "संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा । "
48. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रयाप्त स्तर तक बढ़ गई होती । "
49. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे घरेलू उद्योग की बिक्री पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों पर विचार किया गया है ।
50. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है । नियम 23 में यह उपबंध है कि नियम 11 के उपबंध समीक्षा के मामले में भी आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे । अतः प्राधिकारी ने अनुबंध-11 के साथ पठित आवश्यक परिवर्तनों के साथ नियम 11 के उपबंधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण किया है । चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के तथ्य पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करते समय ध्यान देना अपेक्षित है । प्राधिकारी ने इस बात की

जांच की है कि क्या क्षति पहुंचाने वाले पाटन को समाप्त करने के लिए मौजूदा उपाय पर्याप्त है अथवा नहीं ।

51. क्षति की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों तथा कीमत और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति और पाटन एवं क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी की जांच की जा सके । प्राधिकारी ने मै0 श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल्स लि0 और मै0 भारत कैमिकल्स, जो नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं, से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है । प्राधिकारी ने समस्त आवश्यक क्षति मापदंडों का विश्लेषण कर संगत मुद्दों पर विचार किया है ।

**मात्रात्मक प्रभाव :** पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव :

#### मांग और बाजार हिस्से का निर्धारण

52. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद की मांग अथवा उसकी प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में किया है । इस प्रकार निर्धारित मांग को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है :-

भारत में मांग/खपत	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिक
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	4,561	6,300	6,098	7,560	6,048
सहायक उत्पादों की बिक्री	मी.ट.	7,130	10,151	10,479	12,631	10,105
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	6,385	6,461	7,080	10,834	8,667
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	111	157	28	704	563
कुल मांग/खपत	मी.ट.	18,187	23,069	23,685	31,729	25,383
<b>मांग में बाजार हिस्सा</b>						
घरेलू उद्योग	%	25%	27%	26%	24%	24%
सहायक उत्पाद	%	39%	44%	44%	40%	40%
संबद्ध देश	%	35%	28%	30%	34%	34%
अन्य देश	%	1%	1%	0%	2%	2%

53. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की प्रत्यक्ष खपत में लगातार वृद्धि हुई है । लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद मांग में संबद्ध देश से हुए आयातों का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है ।

**आयात मात्रा और बाजार हिस्सा**

54. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

आयात मात्रा	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिक
चीन जन.गण.	मी.ट.	6,385	6,461	7,080	10,834	8,667
अन्य देश	मी.ट.	111	157	28	704	563
कुल आयात	मी.ट.	6,497	6,618	7,108	11,538	9,230
आयातों में बाजार हिस्सा						
चीन जन.गण.	%	98.3%	97.6%	99.6%	93.9%	93.9%
अन्य देश	%	1.7%	2.4%	0.4%	6.1%	6.1%
कुल आयात	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप में लगातार वृद्धि हुई है । घरेलू बाजार में अधिकांश आयात केवल संबद्ध देश से हुए हैं ।

**उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग**

55. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा मांग में वृद्धि के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद की क्षमता में वृद्धि की गई है । घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी मांग में वृद्धि के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है । तथापि, समूची क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का हिस्सा कमोबेश समान स्तर पर रहा है ।

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिक
स्थापित क्षमता	मी.ट.	6,600	10,400	11,400	14,250	11,400
उत्पादन	मी.ट.	5,593	8,226	9,034	11,201	8,961
क्षमता उपयोग	%	85%	79%	79%	79%	79%
घरेलू बिक्री	मी.ट.	4,561	6,300	6,098	7,560	6,048
मांग	मी.ट.	18,187	23,069	23,685	31,729	25,383

**कीमत प्रभाव — पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**

56. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास और न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित

कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के लिए पाटित आयातों के पहुंच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में करों, रिबेट, छूट और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त कमीशन का समायोजन किया गया है। कम कीमत पर बिक्री क्षति निर्धारण का एक प्रमुख संकेतक है, इसलिए प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत निकाली है और उसकी तुलना पहुंच मूल्य के साथ की है ताकि कम कीमत पर बिक्री की गणना की जा सके। घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर समुचित विचार करने के बाद किया गया है। स्थिति निम्नानुसार है :

### कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

#### कीमत कटौती

57. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के प्रभावों की नीचे जांच की गई है :

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	सूचीबद्ध रु0/किग्रा10	100	97	93	97
पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	177	188	175	157
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	180	191	179	160
पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती					
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	सूचीबद्ध रु0/किग्रा10	100	39	53	158
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	%	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रेंज (%)	5-15	0-10	5-15	15-25
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती					
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	सूचीबद्ध रु0/किग्रा10	100	30	46	166
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	%	***	***	***	***
रेंज	रेंज (%)	5-15	0-10	0-10	15-25

**कम कीमत पर बिक्री**

विवरण	इकाई	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत	रु./किग्रा.	***
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रु./किग्रा.	157
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रु./किग्रा.	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रु./किग्रा.	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	%	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	%	***
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	15-25
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	15-25

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क सहित और रहित, दोनों रूपों में कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क सहित और रहित, दोनों रूपों में आयातों की पहुंच कीमत क्षति रहित कीमत से काफी कम है जिसके परिणामस्वरूप कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक रही है।

**कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण**

58. घरेलू कीमत पर पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभावों की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की प्रवृत्ति की तुलना उत्पादन लागत के साथ की गई है। नीचे दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण बिक्री लागत में वृद्धि होने के बावजूद अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में समर्थ नहीं रहा है।

**क्षति के अन्य मापदंडों की जांच**

59. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव और आयात मात्रा एवं मूल्य, क्षमता, उत्पादन, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग तथा बिक्री के साथ-साथ विभिन्न खंडों के बाजार हिस्सों के साथ मांग की पद्धति जैसे क्षति के प्रमुख संकेतकों की जांच करने के बाद ऐसे अन्य आर्थिक मापदंडों का नीचे विश्लेषण किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का संकेत मिल सके :

लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रवाह ब्याज पूर्व और पश्चात लाभ/हानि

60. निवेश पर आय, ब्याज पूर्व और पश्चात लाभ/हानि तथा नकद प्रवाह को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि	जांच अवधि वार्षिक
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***	***
बिक्री की लागत	सूचीबद्ध रु./किग्रा	100	93	99	106	106
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***	***
बिक्री कीमत	सूचीबद्ध रु./किग्रा	100	97	93	97	100
लाभ/हानि	रु./किग्रा.	***	***	(***)	(***)	(***)
लाभ/हानि	सूचीबद्ध रु./किग्रा	100	174	(25)	(54)	(54)
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	(***)	(***)	(***)
लाभ/हानि	सूचीबद्ध लाख रुपए	100	240	(34)	(90)	(72)
ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***
ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	सूचीबद्ध लाख रुपए	100	186	20	26	21
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसी ई)	%	***	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसी ई)	रेंज (%)	5-15	10-20	0-10	0-10	0-10
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	(***)	(***)
नकद लाभ	सूचीबद्ध लाख रुपए	100	202	4	(36)	(29)

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है वहीं इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2010-11 से घाटा जारी है। जांच अवधि के दौरान नकद लाभ में भारी गिरावट आई है और आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया है। इसी प्रकार, आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में नकारात्मक जांच अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी पर आय में भी भारी गिरावट आई है।

मालसूची

62. निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में वृद्धि हुई है। तथापि, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले जांच अवधि के दौरान इसमें मामूली वृद्धि हुई है।

मालसूची	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी०ट०	213.65	193.50	231.70	228.19

रोजगार एवं मजदूरी

63. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
रोजगार	सं०	354	342	336	367
मजदूरी	लाख रु०	***	***	***	***
मजदूरी	सूचीबद्ध लाख रु०	100	121	147	175

उत्पादकता

64. निम्नलिखित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई है।

विवरण		2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
प्रति दिवस उत्पादकता	मी० ट०	16	24	26	32
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी०ट०/दिवस	16	24	27	31

### ज. पाटन मार्जिन की मात्रा

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक और न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

### झ. वृद्धि

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री तथा उत्पादकता जैसे कुछ आर्थिक मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लाभ, नकद लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय आदि में गिरावट आई है । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा में समग्र रूप से बाजार हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

### ज. कारणात्मक संबंध

67. प्राधिकारी ने इस बात की निम्नानुसार जांच की, कि क्या अन्य ज्ञात ज्ञारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है :

- i. तीसरे देशों से आयात : — प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात नगण्य हैं और इसलिए इनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है ।
- ii. मांग में कमी : — प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि देश में संबद्ध वस्तु की मांग में समूची क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है ।
- iii. खपत की पद्धति :— यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को संबद्ध वस्तु की खपत की पद्धति में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस बारे में कोई अनुरोध किया है ।
- iv. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां :— प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेवार हैं ।
- v. प्रौद्योगिकी विकास :— प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई खास परिवर्तन हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है ।
- vi. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन :— घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत तथा लाभप्रददत्ता को पृथक किया है ।



**पाटन एवं क्षति की संभावना****घरेलू उद्योग के अनुरोध**

68. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी चीन से पेरसिटामोल का पाटन जारी है ।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पेरसिटामोल के पाटन के संबंध में चीन जन.गण. के खिलाफ दो जांचें की हैं । पूर्ववर्ती दोनों जांचों अर्थात् मूल जांच तथा निर्णायक समीक्षा जांच में अत्यधिक पाटन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है ।
- iii. चीन पेरसिटामोल का एक प्रमुख निर्यातक देश है और वह कई देशों को इस उत्पाद का निर्यात कर रहा है । वस्तुतः भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का 99 प्रतिशत केवल संबद्ध देश द्वारा किया गया है । चीन पर दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ जैसे अन्य क्षेत्राधिकारों से पेरसिटामोल पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2011 में की गई अपनी निर्णायक समीक्षा जांच में चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू रखना जारी रखा है ।
- iv. संबद्ध देश से आयातों के कारण भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है । समूची क्षति अवधि में अत्यधिक कीमत कटौती विद्यमान थी । वर्तमान पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी संबद्ध देश से हुए आयात के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है ।
- v. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है । अतः वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने और घरेलू उद्योग द्वारा आयात कीमत पर बिक्री करने का विकल्प चुने जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटा होगा ।
- vi. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी संबद्ध देश के निर्यातकों और उत्पादकों ने पाटित कीमतों पर सामग्री का निर्यात जारी रखा है । इस बात पर विचार करने का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान मामले में शुल्क समाप्त किए जाने से चीन जन.गण. से पाटन में वृद्धि नहीं होगी ।
- vii. अनुरोध है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों के पास संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की व्यापक क्षमताएं हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है । यदि

पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में आगे और वृद्धि होना अवश्यभावी है ।

क्र. सं.	चीन में उत्पादक	क्षमता (मी.ट. प्रति वर्ष)
1.	हेबेई जिहेंग (ग्रुप) फार्मास्युटीकल कं० लि०	25,000
2.	जियानशू गुओहेंग फार्मा कैमिकल कं० लि०	2,500
3.	रंकी ट्रेडिंग कं० लि०	12,000
4.	शंघाई बिलियन कैमिकल कं० लि०	50,000
5.	चंगशू हुआगांग फार्मास्युटीकल कं० लि०,	8,000
6.	जियांगशू वर्ल्ड काइंडली फार्मास्युटीकल कं० लि०,	10,000
7.	वेनझोऊ फार्मास्युटीकल फैक्ट्री	6,000
8.	झेजियांग कांगले फार्मास्युटीकल कं० लि०,	20,000
9.	एक्यूलुआन फार्मास्युटीकल कं० लि०	24,000

viii. आयातों का पहुंच मूल्य वह कीमत है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है । अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादक भारतीय बाजार को आक्रामक ढंग से लक्ष्य बनाएंगे ।

ix. शुल्क लागू किए जाने के बाद ड्राई सैल बैटरी के मामले में घरेलू उद्योग के निष्पादन में अत्यधिक सुधार हुआ था और वह लाभ कमा रहा था । तथापि, वर्तमान जांच में मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है और संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जारी है ।

#### उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

69. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

i. याचिकाकर्ता पाटन की संभावना का मामला बनाने में विफल रहे हैं क्योंकि उन्होंने चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध अत्यधिक क्षमता के ब्यौरे प्रदान नहीं किए हैं ।

- ii. वर्तमान स्थिति एक ऐसा विशेष मामला नहीं है जहां पाटनरोधी शुल्क की अवधि को आगे और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाए जैसा कि ड्राई सैल बैटरियों से संबंधित जांच में माना गया था ।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

70. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है । नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए इस बात का निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लगातार लागू रखने की आवश्यकता है । इस बात की भी जांच करना अपेक्षित है कि क्या लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से क्षतिकारी पाटन को समाप्त करने के नियत उद्देश्य की प्राप्ति होती है । वर्तमान जांच में चूंकि पाटित आयात जारी हैं इसलिए प्राधिकारी से इस बात की जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से उत्पाद के सतत पाटन की संभावना है । तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मूल और वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन अत्यधिक है और जहां तक संबद्ध वस्तु की मांग और कीमत का संबंध है, भारतीय बाजार में अनुकूल बाजारी स्थितियां हैं, प्राधिकारी के पास इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में वृद्धि होगी । वस्तुस्थिति यह है कि पाटनरोधी उपाय लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग के प्रतिकूल भारतीय बाजार में संबद्ध देश की अत्यधिक मौजूदगी बनी रह सकती है ।

71. निम्नलिखित विश्लेषण में शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की संभावना का उल्लेख है :-

#### वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

72. प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन और अब निर्धारित पाटन मार्जिन पर विचार करते हुए यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि निर्यातों को पाटित कीमतों पर किया जाना जारी है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से उनके जारी रहने की संभावना है । पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है । वर्तमान जांच अवधि में आयात मात्रा मूल जांच अवधि से भी अधिक है । इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में आगे और वृद्धि होने की संभावना है । मूल, प्रथम निर्णायक समीक्षा और वर्तमान जांच में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन का स्तर, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभावित पाटन का एक संकेतक है ।

जांच	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
मूल	***	40-50
प्रथम निर्णायक समीक्षा	***	20-30
वर्तमान निर्णायक समीक्षा	***	20-30

ऊपर बताई गई तुलना के अनुसार पाटन मार्जिन के स्तर से यह पता चलता है कि विगत जांचों में लगाए गए पाटनरोधी उपायों से निर्यातक देश के निर्यातकों पर भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन करने पर अंकुश नहीं लगा है ।

#### अन्य देशों द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क

73. दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2011 में संपन्न अपनी निर्णायक समीक्षा जांच में चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू रखना जारी रखा है । दक्षिण अफ्रीका ने 2573 सेंट/किग्रा. की दर से शुल्क लगाया है । चीन में अत्यधिक उत्पादक क्षमता और भारतीय बाजार में वस्तु का पाटन करने की चीन की प्रवृत्ति तथा भारत में बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि भारत में संबद्ध वस्तु के पाटन में और तेजी लाई जाएगी ।

#### भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

74. चीन जन.गण. से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात जिस कीमत पर किया जा रहा है, वह पाटन जारी रहने/उसमें तेजी आने की संभावना की एक संकेतक है । भारत में पहुंच कीमत पर शुल्क सहित और रहित, दोनों रूपों में कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है । इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करने हेतु चीन के उत्पादकों के लिए भारतीय कीमतें और अधिक आकर्षक बन जाएंगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता चीन से बड़े पैमाने पर संबद्ध वस्तु का आयात करने लगेंगे ।

#### चीन में अत्यधिक उत्पादन क्षमता

75. जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है, चीन में संबद्ध वस्तु के कम से कम 9 ऐसे उत्पादक हैं जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता 1.5 लाख मी.ट. से अधिक है । संबद्ध वस्तु का भारतीय उत्पादन चीन की क्षमता के मुकाबले नगण्य है । पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में और चीन के निर्यातों में वृद्धि होने के मद्देनजर चीन के उत्पादक संबद्ध वस्तु के उत्पादन में लगे भारतीय विनिर्माण क्षेत्र पर पूरा कब्जा करने में समर्थ हैं ।

**भारतीय बाजार में चीन जन-गण. का बाजार हिस्सा**

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि सहित समूची क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है ।

**ट. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन—जांच अवधि**

77. प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-111 के अनुसार यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देश से हुए निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और इस प्रकार निकाला गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	चीन का उत्पादक/निर्यातक
घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत	रु./किग्रा.	***
ए डी डी के बिना पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	157
क्षति मार्जिन	रु./किग्रा.	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन % रेंज	रेंज %	15-25

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर निकाला गया क्षति मार्जिन काफी अधिक है ।

**भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**

78. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं । तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहारों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का ह्रास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं हेतु उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या अधिक स्रोत रख सकते हैं ।

79. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः ऐसे पाटन को समाप्त करना है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है और भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करता है जो देश के सामान्य हित में है । इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

### प्रकटन विवरण पश्चात् टिप्पणियां

80. प्रकटन विवरण के पश्चात् उत्पादक/निर्यातक/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- i. प्राधिकारी को हेबाई जीहेंग, चीन के उत्तर को स्वीकार करना चाहिए और उनके लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित करना चाहिए ।
- ii. याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक मेघमणि के बारे में सूचना प्रदान नहीं की गई थी ।
- iii. पान ड्रग्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 15 माह की जांच अवधि के दौरान उन्होंने 1115 मीट्रो पैरासिटामोल का उत्पादन किया है जिसे याचिकाकर्ताओं ने हिसाब में नहीं लिया है ।
- iv. याचिकाकर्ताओं ने भारत में घरेलू उत्पादकों और संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के पास आधार का अभाव है और इसलिए जांच को आगे समाप्त करने की जरूरत है ।

81. प्रकटन विवरण के पश्चात् घरेलू उद्योग की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

- i. निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत काफी कम है ।
- ii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सतत पाटन के कारण लगातार क्षति हो रही है । सतत पाटन, अत्यधिक कीमत कटौती की संभावना और चीन के उत्पादकों के पास बेशी क्षमताओं तथा इन उत्पादकों के निर्यातान्मुखी होने से सामूहिक रूप से यह पता चलता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति और गंभीर हो जाएगी ।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

82. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात् दी गई टिप्पणियां अधिकांशतः पुनरावृत्ति हैं । तथापि, प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों पर नीचे विचार किया गया है :-

- i. जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण सत्यापित आंकड़ों और प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के आधार पर नियमानुसार किया गया है ।

- ii. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि मै0 हेबाई जीहेंग, चीन के लिए पृथक पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के उक्त निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के विलंबित उत्तर को अस्वीकार किया गया था और इसलिए उनके लिए पृथक पाटन के निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता है।
- iii. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में संबद्ध वस्तु के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक मेघमणि के बारे में सूचना याचिकाकर्ताओं ने प्रदान नहीं की थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त घरेलू उत्पादक ने आवेदन का समर्थन किया है।
- iv. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि जांच अवधि (15 माह) के दौरान मै0 पान ड्रग्स ने 1115 मी0ट0 पैरासिटामोल का उत्पादन किया है और याचिकाकर्ताओं ने कुल घरेलू उत्पादन में उक्त आंकड़ों को हिसाब में नहीं लिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने कंपनी रजिस्ट्रार (आर ओ सी) से प्राप्त कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन के आंकड़े लिए हैं। उसमें प्रदत्त सूचना में उल्लेख है आई टी सी 0030049005 के अंतर्गत वर्गीकृत "सर्वोच्च योगदानकर्ता उत्पाद या सेवा की मात्रा", जो "पैरासिटामोल की गोलियों" से संबंधित पाया गया है, जो वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तु नहीं है। वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तु बल्क रूप में एक कार्बनिक रसायन पैरासिटामोल है।
- v. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उत्पादकों और भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के बारे में याचिकाकर्ताओं ने गलत तर्क प्रस्तुत किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच मै0 श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल लि0 और मै0 भारत कैमिकल द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। जांच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों अर्थात् पारा प्रोडक्ट्स, सारा एक्सपोर्टर्स लि0, पान ड्रग्स लि0, पैरामाउंट हेल्थ केयर लि0, फार्मसंस एनालजेसिक्स, अल्फा ड्रग्स लि0 और ग्रेन्यूल्स इंडिया लि0 को जांच शुरुआत संबंधी सूचना की प्रति उपलब्ध कराई गई थी। यद्यपि, मै0 सारा एक्सपोर्टर्स, मै0 पारा प्रोडक्ट्स, मै0 फार्मसंस एनालजेसिक्स और मै0 मेघमणि यूनीकेम ने आवेदन का समर्थन किया है तथापि, अन्य ने न तो आवेदन का समर्थन किया है और न ही उसका विरोध। प्राधिकारी द्वारा इस जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में आधार के मुद्दे की पर्याप्त जांच कर उसका समाधान किया गया है और प्राधिकारी ने पहले से ही यह माना है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में आवेदकों अर्थात् मै0 श्रीकृष्णा फार्मास्युटीकल लि0 और मै0

भारत कैमिकल्स तथा समर्थनकर्ता मै0 सारा एक्सपोर्ट्स, मै0 पारा प्रोडक्ट्स, मै0 फार्मसंस एनालजेसिक्स और मै0 मेघमणि यूनीकैम का हिस्सा संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में एक बड़ा भाग बनता है और वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए घरेलू उद्योग हैं ।

### निष्कर्ष :

83. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने तथा पाटन एवं क्षति जारी रहने की संभावना की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- i. समूची क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात का स्तर काफी अधिक रहा है और जांच अवधि के दौरान इसका एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है ।
- ii. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन हो रहा है और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया गया है तो पाटन जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की संभावना है ।
- iii. पाटनरोधी शुल्क सहित और रहित दोनों रूपों में कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री अत्यधिक सकारात्मक रही है ।
- iv. जांच अवधि में लाभ, निवेश पर आय, नकद लाभ आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है जबकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद इसमें सामान्यतः सुधार आना चाहिए था ।
- v. यद्यपि, जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने उत्पादन, घरेलू बिक्री तथा उत्पादकता जैसे कुछ आर्थिक मापदंडों में कुछ सकारात्मक वृद्धि प्रार्थित की है तथापि इन आर्थिक मापदंडों में सुधार मुख्यतः लागू पाटनरोधी उपायों के कारण हुआ है ।
- vi. पाटनरोधी उपाय लागू होने के बावजूद बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही है और पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन अत्यधिक रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है ।



- vii. समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा काफी अधिक रही है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि में उसमें भारी वृद्धि है। अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री के कारण तथा चीन में क्षमता और भारत में मांग को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित आयात की मात्रा में आगे और वृद्धि होने की संभावना है।
- viii. पूर्ववर्ती जांचों में पाटन मार्जिन की मात्रा और वर्तमान पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर निर्यात जारी रहा था जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी। पाटनरोधी उपायों के बावजूद संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन निर्बाध रूप से जारी है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो संबद्ध वस्तु के पाटन में वृद्धि होने की पूरी संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होगी।

#### सिफारिशें

84. उपर्युक्तानुसार निष्कर्ष निकालने के बाद प्राधिकारी का मत यह है कि चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी उपाय में संशोधन करना और उसकी अवधि बढ़ाना अपेक्षित है जैसाकि निम्नलिखित शुल्क तालिका में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों के संबंध में निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।
85. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखे हुए प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क तालिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके।

## शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	29222933	पेरासिटामोल	समस्त श्रेणी	- वही -	चीन जन.गण.	कोई	कोई	787	मी.ट.	अम.डा.
2.	- वही -	- वही -	- वही -	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	787	मी.ट.	अम.डा.
3.	- वही -	- वही -	- वही -	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	787	मी.ट.	अम.डा.

## ख. आगे की प्रक्रिया :

86. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे ।
87. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2013

**Final Findings**

**Subject : Sunset Review of the Anti-dumping Duty imposed on imports of Paracetamol, originating in or exported from China PR.**

**F. No. 14/1009/2012-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules) thereof;

**A. Background of the Case**

1. WHEREAS, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had initiated the original anti-dumping investigation concerning imports of Paracetamol (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred as the subject country), vide Notification No. 60/1/2000-Customs dated 30<sup>th</sup> January, 2001. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification dated 16<sup>th</sup> April 2001 and the provisional anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 89/2001-Customs dated 6<sup>th</sup> September 2001. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No. 60/1/2000-DGAD dated 22<sup>nd</sup> January 2002, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Department of Revenue vide Notifications 29/2002-

Customs dated 27<sup>th</sup> March 2002 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2. AND WHEREAS, in the 1<sup>st</sup> sunset review investigation, vide final finding Notification No. 15/20/2006-DGAD dated 23<sup>rd</sup> July, 2007, the Authority concluded that the cessation of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, will lead to continuation or recurrence of dumping and injury, and recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods. Accordingly, definitive anti-dumping duty was extended on the subject goods vide Customs Notification No. 99/2007-Customs dated 3<sup>rd</sup> September, 2007.
3. Whereas, M/s Sri Krishna Pharmaceutical Ltd, Hyderabad and Bharat Chemicals, Mumbai have jointly filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
4. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 14/1009/2012-DGAD dated 28.08.2012 to review the need for continued imposition of the duties in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country has been extended up to 2<sup>nd</sup> September, 2013 by the Central Government vide Notification No.42/2012-Customs (ADD) dated 19.09.2012. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods originating or exported from the subject country.

#### **B. Procedure**

5. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

- a. The embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
- b. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
- c. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers/exporters in China PR (whose names and addresses were made available to the Authority by the Domestic Industry) as follows and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):
  - i. Anhui Bayi Chemical Industry Co. Ltd.
  - ii. Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co. Ltd.
  - iii. Wenzhou Pharmaceutical Factory,
  - iv. Changshu Huagang Pharmaceutical Co. Ltd.
  - v. Hebei Jiheng Group Co. Ltd.
  - vi. Hebei Jiheng (Group) Pharmacy Co. Ltd.
  - vii. Huzhou Beigang Enterprises Group Corp.
  - viii. Zhongxin Pharma Tiangin Xinxin Pharmaceutical
  - ix. Jiangsu Guotal International Group Co. Ltd.
  - x. Liaoyuan City Baikang Pharmaceutical
  - xi. Shanghai Bailion Chemicals Co., Ltd.
- d. A Market Economy Treatment (MET) questionnaire was forwarded to all the known exporters and embassy of China PR with a request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time. While for the purpose of initiation the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed known exporters that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of para 7 and para 8 of Annexure I of Anti-Dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were therefore requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to cooperative exporters/producers.
- e. No Questionnaire response was received from any producer/exporter from the subject country within the prescribed

time limit. A much belated exporter questionnaire was filed by M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd, which was not accepted by the Authority. However, the submission made by above named Chinese company have been addressed in this final finding.

- f. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the following known importers (whose names and addresses were made available to the Authority by the Domestic Industry) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):
- i. Ajanta Pharma Ltd.
  - ii. Cipla Ltd
  - iii. Ciron Drugs & Pharmaceuticals P Ltd.
  - iv. Flamingo Pharmaceuticals Ltd.
  - v. Indoco Remedies Ltd.
  - vi. Maneesh Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
  - vii. Mangalam Drugs & Organics Ltd.
  - viii. Medopharm,
  - ix. Techno Economic Services P Ltd.
  - x. Healthy Life Pharma Pvt. Ltd.
  - xi. Glow Export Trading Pvt. Ltd.
  - xii. IPCA Labs Ltd.
  - xiii. Triton Laboratorial Ltd.
  - xiv. Vamsi Labs Ltd.
  - xv. Srinivasa Agro Industries and Drugs Ltd.
- g. Apart from the applicants, the Authority also provided a copy of the initiation notification to other domestic producers of the subject goods, as per the information provided in the application as below
- i. Para Products
  - ii. Sara Exports Ltd.
  - iii. PAN Drugs Ltd.
  - iv. Paramount Health Care Ltd.
  - v. Farmson Analgesics
  - vi. Alpha Drugs Ltd.
  - vii. Granules India Ltd.
- h. The non-confidential version of the evidences presented by the interested parties were made available by the Authority to the interested parties in the form of a public file and kept open for inspection by them as per Rule 6(7).

- i. Exporters, producers and other interested parties who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these statements on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
- j. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the injury period including POI.
- k. Information was sought from the applicants to determine non-injurious price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India.
- l. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry in terms of the principles laid down in Annexure III to the Rules.
- m. The Authority held a public hearing on 11<sup>th</sup> June, 2013 to hear the interested parties orally. The interested parties present at the time of hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally and were also given an opportunity to file rejoinder to the views expressed by other interested parties.
- n. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been considered in this final finding, to the extent considered relevant by the Authority;
- o. On the spot verification of the data/information furnished by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary.
- p. Investigations have been carried out by the Authority for the period of investigation (POI) starting from 1<sup>st</sup> January, 2011 to 31<sup>st</sup> March, 2012 (15 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods Apr'08-Mar'09, Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11 and the POI.
- q. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts of the investigation were disclosed by the Authority to the known interested parties vide letter dated 19<sup>th</sup> August, 2013 and comments received on the same, to the extent considered relevant by the Authority, have been considered in this Finding.

- r. \*\*\* in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- s. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.47.66 = 1 US\$.

**C. Scope of Product under consideration and like article**

- 6. The product under consideration, in the original as well as the 1<sup>st</sup> SSR investigation and the present sunset review investigation, is "Paracetamol also known as acetaminophen", originating in or exported from China PR. The present investigation being a sunset review, the investigation covers the product covered in the original investigation as well as the 1<sup>st</sup> SSR investigation.
- 7. Paracetamol is an odourless white crystalline powder. Its chemical formula is C<sub>8</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>2</sub>. Paracetamol is a bulk pharmaceutical active ingredient, displaying analgesic and antipyretic properties. It is used in a number of Rx and OTC drug formulations in the form of powders, granules, injectibles and tablets. Paracetamol is an organic chemical and is classified under Custom sub-heading 2922.2933 of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- 8. The present investigation being a sun set review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the earlier investigations. Moreover, none of the interested parties has made any submission in this regard.

**D. Domestic Industry and Standing**  
**Submissions by the Domestic Industry**

- 9. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
  - i. Sri Krishna Pharmaceutical Ltd., Hyderabad and Bharat Chemicals, Mumbai have filed the petition and M/s Sara Exports, M/s Para Products, M/s Farmson Analgesics and Meghmani Unichem have supported the application.



- ii. There is no legal requirement that companies who participated at the time of original investigation should participate in the present investigation. There is no obligation on the petitioner to seek participation of those domestic producers who had participated at the time of original investigation. Rights of petitioners cannot be curtailed because of non-participation of other domestic producers.
- iii. Production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production and therefore, they are entitled to seek extension of present anti-dumping duty.
- iv. As per the Rules, only requirement is that the production of the participating companies should constitute a major proportion of Indian production. A major production does not mean more than 50%. The Designated Authority has recorded findings in earlier cases, such as Zinc oxide on the basis of information for domestic industry in respect of those companies whose collective output was less than 50%.
- v. Petitioners have provided information with regard to petitioner companies. As regards other domestic producers, petitioners have provided information as is reasonably available to them. There is no publically available information with regard to other companies named by the exporters.
- vi. Post initiation, M/s Farmsons Analgesics provided its costing and injury information relevant to the present investigations. The said information has been filed vide letter dated 9<sup>th</sup> July, 2013.
- vii. Granules India Ltd. is a 100% EOU and does not have significant sales in the domestic market.
- viii. Alpha Drugs India Ltd. has been merged with Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. (PCPL) and not a producer of paracetamol.
- ix. Pan Drugs Ltd and Paramount Healthcare Ltd do not produce and supply paracetamol in the domestic market.
- x. Finding issued by the South African Authority in the matter of sunset review of the anti-dumping duties on acetaminophen originating in or imported from India was issued on 17.02.2007. The investigation period for dumping was from 1 July 2004 to 30 June 2005, and the injury investigation involves evaluation of data for the period 1 July 2002 to 30 June 2005. It is relevant to note that the said finding was issued even prior to first sunset review conducted by the Indian

Designated Authority. The Indian Designated Authority issued first sunset review finding vide notification dated 23.07.2007.

- xi. With regard to 37 companies of paracetamol named in the South African finding, the South African Authority notes that not even one company other than Sri Krishna Pharmaceutical Ltd. identified itself nor responded to the South African Authority. The final findings issued by South African authority is not at all a conclusive proof to decide whether they are producer of subject goods in the present investigation.
- xii. It has been claimed by the opposite interested parties that information about the following producers are available in public domain, and these companies are named in the South Africa findings
  - i. Alpha Remeies Ltd.
  - ii. Dines Pharmaceuticals
  - iii. G. Amphray Laboratories
  - iv. JamhikDyechem Industries
  - v. Triochem Products Ltd.
  - vi. Zoom Organic Ltd.
- It is submitted that none of the above named parties are producers of subject goods. At the most they are only manufacturing paracetamol tablets, which is a not subject goods in the present investigation.
- xiii. With regard to further claim that Meghmani Unichem is also a major producer of subject goods with the capacity of 7500 MT per year, as per web information, Meghmani Unichem Ltd. is an SEZ unit, established in 2011, It is submitted that there is no publically available information when Meghmani Unichem started its commercial production, whether they have sold any quantity in the domestic market being SEZ unit..
- xiv. Further as per web information dated 07.03.2012, the Gujarat Pollution Control Board (GPCB) officials have issued closure notice with immediate effect to the Dahej plant of Meghmani Unichem Limited, discharging hazardous effluents directly into the GIDC pipeline without treatment.
- xv. It is submitted that, without any conclusive evidence, it cannot be said that Meghmani Unichem is producer of subject goods selling in the domestic market in the relevant period and their alleged production can

be considered as eligible domestic production for the purpose of determining standing of the petition.

- xvi. The scope of the product under consideration is only bulk drug and excludes formulations. Moreover initiation notification of the present investigation was published in the gazette. Meghmani organic has never responded to initiation notification. The company has not claimed before the Designated Authority that they are also domestic manufacturer of subject goods and have produced the product under consideration in the period of investigation
- xvii. Notwithstanding, even if production of Meghamani Organics is considered to the extent of the claim made, it may be noted that the production of the petitioners then shall constitute 39% of Indian production and production of petitioners with supporters shall constitute 74% of the Indian production.
- xviii. Imports were made by a related unit of one of the petitioner company, M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd and imports have been made under advance license. The Designated Authority has held that imports made under advance license do not debar a company from being treated as a domestic industry.
- xix. The scope of domestic industry and standing are not relevant in a sunset review.
- xx. In view of the fact that production of petitioner companies not only meet the requirement of standing, but also constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

**Submission made by other interested parties.**

10. The following submissions have been made by M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd:

- i. The producers who had represented the domestic industry during the initial investigations have not participated in the present petition. There is no analysis or reasons as to why those producers who were petitioners in the earlier investigations have not participated in the present petition.
- ii. The petitioners have not included the production details of other major domestic producers, namely Granule India Ltd., Alpha Drugs India Ltd.

Pan Drugs India Ltd, Paramount Health Care Ltd., and Farmson Analgesics.

- iii. The Total production of subject goods in India is 47651MT and not 21401MT as claimed by the petitioners. Considering the actual total production in India, the petitioners share in total Indian production is only 23.51%.
- iv. There is no justification to exclude two big producers (Granules India and Farmson Analgesics) from the purview of domestic industry.
- v. One of the related units of Sri Krishna Pharmaceuticals has imported the subject goods from China PR and thus it cannot form part of Domestic Industry.
- vi. In term of 23(1B) of AD Rules, standing of domestic industry is an essential criteria in sunset review investigation.
- vii. As per the South African finding there are 37 producers of Paracetamol in India. The present petition does not provide the details.
- viii. The details of production of Paracetamol by Alpha remedies ltd, Dinesh Pharmaceutical, G. Ampharay Laboratories, Jamhik Dyechem Industries, Trichem Products Ltd, Zoom organic Ltd and Meghmani Unichem as available in the public domain, have not been provided in the petitioner.
- ix. Since the petitioners lack standing, the injury, causal link and likelihood of injury as claimed by the petitioner is faulty.

#### **Examination by Authority**

11. Sri Krishna Pharmaceutical Ltd., Hyderabad and Bharat Chemicals, Mumbai have filed the petition. Subsequently M/s Sara Exports Ltd, M/s Para Products Pvt Ltd, M/s Farmson Analgesics (A Unit of Pharmson Pharmaceutical Gujarat Pvt Ltd) and M/s Meghmani Unichem LLP have supported the application. The submissions made by the interest parties with regard to the standing of domestic industry are addressed below:
12. As regards the contention that the producers who had represented the domestic industry during the initial investigations have not participated in the present sunset review, the Authority notes that there is no provision under the Rules to mandate for such industries to come before Authority.

13. As regard the contention that other major domestic producers, namely Granule India Ltd., Alpha Drugs India Ltd. Pan Drugs India Ltd, Paramount Health Care Ltd., and Farmson Analgesics, have not participated in the present sunset review, the Authority notes that initiation notification was provided to the said industries, requesting to provide relevant information. But the said industries did not respond. However subsequently M/s Farmson Analgesics provided costing and injury information. The Authority further notes that as per information provided by the domestic industry, Granules India Ltd. is a 100% EOU and does not have significant sales in the domestic market. Moreover in the first sunset review Authority excluded M/s Granules India Ltd being an importer of the subject product over the entire injury period.
14. As regard the contention of opposite interested parties that the total production of subject goods in India is 47651MT, the Authority notes that such claim is unsubstantiated. Moreover, the other domestic producers as stated above, who were requested to provide relevant information post initiation have not come before the Authority.
15. As regard the contention of opposite interested parties that one of the related units of Sri Krishna Pharmaceuticals has imported the subject goods from China PR and thus it cannot form part of Domestic Industry, the Authority notes that such a position does automatically disqualify a domestic producer to be considered as domestic industry, unless it is proved that concerned domestic producer is a beneficiary of dumping of the subject goods by the subject country. In the present case the imports made by the related party of Sri Krishna Pharmaceuticals is an acknowledged fact and are stated to have been imported only 238 MT of Paracetamol during the POI under duty free schemes. The duty free imports made under duty exemption are meant for manufacturing goods for export purpose and such duty free imports cannot be traded in the domestic market.
16. The South African findings concerning the subject goods, as relied by opposite interested parties, pertains to the year 2007. The said findings had merely identified 37 Indian producers without any substance. Moreover, Sri Krishna Pharmaceutical Ltd, one of the petitioners in the present sunset review, was the only Indian producer who had participated in the South African investigation. Moreover, the interested parties have themselves not provided any conclusive proof to justify their claim that they are as many as 37 producers of subject goods in India engaged in production and sale in the domestic market.

17. The Authority notes that in the present sunset review, the application has been jointly filed by M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. and M/s Bharat Chemicals. M/s Sara Exports, M/s Para Products and M/s Meghmani Unichem LLP have supported the application. Another domestic producer of the subject goods namely M/s Farmson Analgesics, one of the constituent of the domestic industries in the first sunset review, has also supported the application and provided costing and injury information. The remaining other producers, if any, did not respond to the Authority's request to provide information. Moreover, there is no domestic producer of the product opposing the present investigation. The details of the eligible Indian production as provided by domestic industry are given below:

Particulars	UOM	POI		As per petition	
		Production	Share	Production	Share
Petitioner	MT	11,201	47.34	8,779	46.26
Bharat Chemicals	MT	***	***	***	***
Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd.	MT	***	***	***	***
Other Producers supporting applicant	MT	12,459	52.66	10,200	53.74
Farmson Analgesics	MT	***	***	***	***
Para Products Pvt. Ltd.	MT	***	***	***	***
Sara Exports Ltd.	MT	***	***	***	***
Meghamani Unichem LLP	MT	***	***	***	***
Total Indian Production	MT	23,660	100.00	18,979	100.00

In view of the above position and having regard to the Rules, the Authority considers M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. and M/s Bharat Chemicals account for a major proportion in the Indian production of the subject goods and constitute domestic industry satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

#### **E. Miscellaneous Issues**

##### **Submissions by the Domestic Industry**

18. The following are the miscellaneous submissions made by the domestic industry:

- i. The Authority has rightly rejected the belated response filed by M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd.
- ii. In view of the above reason, submissions made by the exporter present at the time of oral hearing should not be accepted/ entertained by Designated Authority.
- iii. According to WTO decision in the matter of US- Sunset Review of AD measures on OCTG from Argentina the interested parties under Articles 6.1 and 6.2 do not provide for "indefinite" rights, so as to enable

respondents to submit relevant evidence, attend hearings, or participate in the inquiry as and when they choose.

19. The following are the miscellaneous submissions made by other interested parties

- i. Questionnaire Response filed by M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd should have been accepted as they are the only exporter participating in the investigation.
- ii. There is no substantive statutory time limit under the Indian Anti-dumping law that responses cannot be accepted after the time limits prescribed by the Authority.
- iii. Excessive confidentiality claimed by the petitioner. The petitioners have not disclosed a lot of information such as the details of production of the four other domestic producers, volume of imports and its analysis, annual accounts etc.

#### **Examination by Authority**

20. The Authority notes that M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd filed response at a much belated stage and did not accord any reasonable and satisfactory explanation for submitting such belated response. It is noted that the right to participate in an investigation cannot be unlimited. The Authority is not required to condone delay without even justifiable reasons being afforded for delaying the response.

21. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible. (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

22. The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to "respective interested parties" only, while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests.
23. With regard to the contention of the interested parties that consolidated information of domestic industry should not be allowed to be kept confidential, the Authority notes that if any consolidated data, if disclosed, may enable the interested parties to derive the confidential constituent data, the same cannot be revealed in the best interest of the interested parties.
24. As regards non-disclosure of the dumping margin calculation at the stage of preliminary finding, the Authority notes that such information is disclosed to the respective interested parties only at the stage of disclosure.

#### **F. Determination of Dumping Margin, Normal Value and Export Price**

25. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. None of the producer/exporter from China PR has co-operated in this investigation by filing their Questionnaires' responses, except questionnaire response filed by M/s Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co. Ltd. which has been rejected on the ground of being submitted at a belated stage.



**Submissions made by the domestic industry**

26. It has been contended by the domestic industry that China PR should be treated as non-market economy country, *inter alia*, stating that:

- i. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity – The Designated Authority and the EC has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in such cases. It is being held that it is not only the question of past interferences alone, but also possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti-dumping duties that is relevant to market economy treatment.
- ii. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values – “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The fact that such prices are comparable to the price prevailing in China is grossly insufficient.
- iii. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establish that their books are audited in line with international accounting standards – market economy treatment must be rejected in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS). The requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report.
- iv. Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied – market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. This situation is just the opposite of the test required for material injury. It is well acknowledged position that a positive finding of injury can be recorded even if one single parameter established injury. Thus, while one parameter is sufficient to establish existence of injury, failure to pass one single parameter is sufficient to reject the claim of market economy status.

- v. Onus/obligations – it is not for the Authority to establish that the Chinese companies are indeed operating under market economy environment and is entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
- vi. Response from group as a whole – Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
- vii. Transformation – In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.

27. USA is a developed country does not imply that USA cannot be treated as a surrogate country. The European Commission has treated USA as a surrogate country in several cases.

**Submission made by producer/exporter/importers/other interested parties**

28. USA may not be considered as the surrogate country for calculation of Normal Value as it is a developed country.

**Examination of Market Economy claims in respect of China PR by the Authority**

29. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters/producers in terms of the AD Rules.

30. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s) /producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/ producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/ sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of

paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether: -

- the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

31. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; none of Chinese producers/exporters has submitted the questionnaires' responses including the market economy questionnaire's response and sought to rebut the non-market economy presumption. Since none of the Chinese companies have claimed market economy treatment, the Designated Authority has not determined whether any of the Chinese producers could be granted market economy treatment.

#### **Determination of Normal value in respect of Exporters / Producers from China**

32. The domestic industry had proposed USA as the appropriate surrogate country for the purpose of calculating normal value in China and had furnished some evidence with regard to price of the subject goods in USA during the period of investigation. In an alternate to the price from a market economy third country, the domestic industry has determined normal value as the price payable in India, considering the cost of production in India, duly adjusted to include selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

33. The Authority notes that in terms of para 7 of the Annexure-I of the Rules, due account should be taken of the level of development of the market economy third country while selecting an appropriate market economy third country. Keeping in view the differential levels of economic development between China PR and USA and the level of development of the subject product, the Authority does not consider USA as an

appropriate market economy third country for China PR and constructed normal value on the basis of cost of production in India

34. As none of Chinese producers and exporters has submitted the questionnaires' responses; the Authority has estimated the Normal value in China PR on the basis of Para-7 to Annexure-I to the AD Rules.

35. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

*"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments".*

36. None of the exporters/producers from the subject country has cooperated with the Authority and responded to the present investigation. Further none of the interested parties has provided any other alternate basis as defined in the Rules on which normal value can be determined. In view of the above position and considering China as a non-market economy, the Authority has determined the normal value in accordance with para 7 of Annexure I of the AD Rules. In absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of AD Rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method "other reasonable basis". The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis of the cost of production in India, duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit and considering the international prices of major raw materials. Accordingly, the constructed normal value for Chinese exporters is determined as US\$ \*\*\* per Kg.

**EXPORT PRICE**

37. Since no response has been received from any producer/exporter of the subject goods from China PR; the Authority has determined Export Price as per 'facts available' in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. For this purpose, the volume of imports as per DGCI&S data has been relied upon. The adjustments to the CIF prices have been made as per facts available on record. Accordingly, export price has been adjusted for ocean freight, Marine insurance, Bank charges, Commission, port expenses in China, and inland freight. Based on the above data the net ex-works export price of the exports from China PR to India is determined as US\$\*\*\* per Kg.

**Determination of Dumping Margin - POI**

38. Comparing the normal values and export price at ex-factory level as determined above, the dumping margin for the producers/exporters of subject country is determined as below:

Particulars	US\$/Kg	Rs./Kg
Normal Value	***	***
Export Price	***	***
Dumping Margin	***	***
Dumping Margin %	***	***
Range %	20-30	20-30

**G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****Submissions by the domestic industry**

39. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- There is continued dumping of the product under consideration from China;
- Dumping of the product under consideration is likely to intensify from subject country should the current anti-dumping duty be revoked;
- Volume of imports is quite significant in relation to production and consumption in India despite existing anti-dumping duties;
- Price undercutting is significantly positive;
- The performance of the domestic industry has not improved even after the imposition of anti-dumping duty. Thus, in the event of cessation of current anti-dumping duty and if Domestic Industry chooses to sell at

- import prices, the Domestic Industry would suffer significant financial losses
- f) The cost of sales has increased in the POI, whereas the selling price has decreased.
  - g) With the increase in demand of the subject goods and imposition of anti dumping duty, domestic industry enhanced its capacity to cater the growing demand. However, the capacity utilization has declined.
  - h) Domestic sales of the domestic Industry shows decline in the period of investigation after achieving certain levels. Production of the domestic Industry has declined in the POI.
  - i) Profit, cash profit and return on investment improved until 2009-10 and thereafter started declining, which has further gone down to negative levels in the period of investigation.
  - j) Performance of the domestic industry deteriorated in terms of inventories, market share, profits, return on investments, cash flow.
  - k) Performance of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization, Domestic sales suffered when compared to changes in demand.
  - l) Performance of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow, etc. has deteriorated in the current Period of Investigation, whereas the same should have improved after imposition of anti dumping duties.
  - m) The domestic industry has not yet recovered from the past ill effects of dumping and revocation of anti dumping duty shall imply intensified injury to the domestic industry in future.
  - n) Despite rising demand and such low prices being offered by the Domestic Industry, the inventories are significant. Sales volumes have not increased in proportion to the demand in the Country, whereas the domestic industry had expected to increase its sales beyond the rate of increase in the demand.

**Submissions made by the producer/ exporter/ importer/ other interested parties**

40. the following submissions with regard to the injury and causal link have been submitted by the opposite interested parties:
- a) The determination of injury is misleading as it is only on the basis of two minority producers.
  - b) Majority of imports during the POI are under duty free schemes. The duty free imports have no impact on domestic market and therefore no need to extend the ADD.

**Examination by the Authority**

41. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure—II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
42. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
43. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provide that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has therefore determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the fact of existing anti-dumping duties on the on the imports of subject goods from China PR is required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether existing measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
44. The opposite interested parties have claimed that majority of the imports of the subject goods during the POI are under duty free schemes. However, they have not substantiated their claim by providing evidence. The Authority notes that the following injury analysis shows the state of the domestic industry and the injury caused by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

**Volume Effects of Dumped Imports: Import volumes and market shares****Examination by the Authority**

45. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
46. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
47. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows: *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*
48. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports



on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to suppress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

49. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
50. The present investigation is Sun Set Review investigation of anti-dumping duties in force. Rule 23 provide that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis basis in case of a review as well. The Authority has therefore determined injury to the domestic industry considering, mutates mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers that the fact of existing anti-dumping duties on imports of the product from China PR is required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether existing measure is sufficient to counteract the dumping which is causing injury.
51. For the purpose of assessing present state of injury, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd and M/s Bharat Chemicals, constituting domestic industry under the Rules. The Authority has addressed the relevant issues by undertaking analysis of all mandatory injury parameters.

**VOLUME EFFECT:** Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry:

#### **Assessment of Demand and market share**

52. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian

Producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table below.

Demand/ Consumption in India	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	POI Annualised
Sales of Domestic Industry	MT	4,561	6,300	6,098	7,560	6,048
Sales of supporting Producers	MT	7,130	10,151	10,479	12,631	10,105
Import from Subject Country	MT	6,385	6,461	7,080	10,834	8,667
Import from Other Countries	MT	111	157	28	704	563
Total Demand/ Consumption	MT	18,187	23,069	23,685	31,729	25,383
<b>Market share in Demand</b>						
Domestic Industry	%	25%	27%	26%	24%	24%
Supporting producers	%	39%	44%	44%	40%	40%
Subject Country	%	35%	28%	30%	34%	34%
Other Countries	%	1%	1%	0%	2%	2%

53. It is noted that the apparent consumption of the subject goods has consistently increased over the injury period. Market share of the imports from subject country in demand has remained significant in spite of the anti-dumping duties in force.

#### Import Volume & market share

54. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Import Volume	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	POI Annualised
China PR	MT	6,385	6,461	7,080	10,834	8,667
Other Countries	MT	111	157	28	704	563
Total Imports	MT	6,497	6,618	7,108	11,538	9,230
<b>Market Share in Imports</b>						
China PR	%	98.3%	97.6%	99.6%	93.9%	93.9%
Other Countries	%	1.7%	2.4%	0.4%	6.1%	6.1%
Total Imports	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

The Authority notes from the data given in the table above that there have been consistent increase in the imports in absolute terms from the subject country. Majority of the imports into the domestic market is from the subject country alone.

### **Production, capacity and capacity utilization**

55. The Authority notes from the table below that capacity for the product under consideration has been increased by the domestic industry in line with the increase in demand. Production and Sales of the Domestic Industry has also increased in proportion to the increase in demand. However share of domestic industry has remained more or less at the same level throughout injury period.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	POI Annualised
Installed capacity	MT	6,600	10,400	11,400	14,250	11,400
Production	MT	5,593	8,226	9,034	11,201	8,961
Capacity Utilization	%	85%	79%	79%	79%	79%
Domestic Sales	MT	4,561	6,300	6,098	7,560	6,048
Demand	MT	18,187	23,069	23,685	31,729	25,383

### **Price Effect - Price effect of dumped imports and impact on domestic industry:**

56. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission offered by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

**Price Undercutting and Underselling:****Price Undercutting**

57. The price undercutting/underselling effects are examined below:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Net Sales realization	Rs./Kg	***	***	***	***
Net Sales realization	Index Rs/kg	100	97	93	97
Landed value without ADD	Rs./Kg	177	188	175	157
Landed value with ADD	Rs./Kg	180	191	179	160
<b>Price Undercutting without ADD</b>					
Price Undercutting without ADD	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting without ADD	Index Rs/kg	100	39	53	158
Price Undercutting without ADD	%	***	***	***	***
Price Undercutting without ADD	Range (%)	5-15	0-10	5-15	15-25
<b>Price Undercutting with ADD</b>					
Price Undercutting with ADD	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting with ADD	Index Rs/kg	100	30	46	166
Price Undercutting with ADD	%	***	***	***	***
Range	Range (%)	5-15	0-10	0-10	15-25

**Price Underselling**

Particulars	Unit	POI
Non injurious price of the domestic industry	Rs/Kg	***
Landed value with ADD	Rs/Kg	
Landed value without ADD	Rs/Kg	157
Price Underselling with ADD	Rs/Kg	***
Price Underselling without ADD	Rs/Kg	***
Price Underselling with ADD	%	***
Price Underselling without ADD	%	***
Price Underselling with ADD	Range %	15-25
Price Underselling without ADD	Range %	15-25

The Authority notes that landed price of imports is far below the selling price of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting, both with and

without anti-dumping duty. Furthermore, the landed price of imports both with and without anti-dumping duty is substantially less than the non-injurious price, thus resulting in positive price underselling.

### **Price Suppression and Depression**

58. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data given below shows that the domestic industry has not been able to increase its selling price despite increase in the cost of sales due to the dumped imports.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Cost of Sales	Index	100	93	99	106
	Rs./kg				
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***
Selling price	Index	100	97	93	97
	Rs./kg				
Landed value without ADD	Rs/Kg	177	188	175	157
Landed value with ADD	Rs/Kg	180	191	179	160

### **Examination of other Injury Parameters**

59. After having examining the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry are analyzed hereunder:

### **Profit/loss, return on investment and cash flow**

60. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI	POI Annualised
Cost of Sales	Rs/kg	***	***	***	***	***
Cost of Sales	Index	100	93	99	106	106
	Rs./kg					

Selling Price	Rs/kg	***	***	***	***	***
Selling Price	Index	100	97	93	97	100
	Rs./kg					
Profit/loss	Rs./kg	***	***	(***)	(***)	(***)
Profit/loss	Index	100	174	(25)	(54)	(54)
	Rs./kg					
Profit/loss	Rs. Lakh	***	***	(***)	(***)	(***)
Profit/loss	Index	100	240	(34)	(90)	(72)
	Rs.Lakh					
Profit before interest and tax	Rs. Lakh	***	***	***	***	***
Profit before interest and tax	Index	100	186	20	26	21
	Rs.Lakh					
Return on capital employed (ROCE)	%	***	***	***	***	***
Return on capital employed (ROCE)	Range (%)	5-15	10-20	0-10	0-10	0-10
Cash Profit	Rs. Lakh	***	***	***	(***)	(***)
Cash Profit	Index	100	202	4	(36)	(29)
	Rs.Lakh					

61. The Authority notes that while the cost of sales of the domestic industry is showing increasing trend during the POI as compared to the base year, the selling price of the domestic industry is showing decreasing trend during the same period. The domestic industry continues to suffer losses from 2010-11 onwards. The cash profit during the POI has declined significantly and has reached negative levels as compared to the base year as well as the immediate preceding year. Similarly, the ROCE has also declined significantly during the POI as compared to the base year as well as the immediate preceding year.

#### Inventories:

62. The data given in the table below shows that the inventory position of the domestic industry during the POI has increased as compared to the base year. However, the same has decreased marginally during the POI vis-à-vis the immediate preceding year.

Inventories	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Average stock	MT	213.65	193.50	231.70	228.19

**Employment and wages**

63. From the table given below, the Authority notes that both the employment and wages of the domestic industry has increased in the POI as compared to the base year.

Particulars	Unit	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Employment	Nos	354	342	336	367
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***
Wages	Index Rs.Lakh	100	121	147	175

**Productivity**

64. The Authority notes from the table below that productivity of the domestic industry has increased sharply during the POI as compared to the base year.

Particulars		2008-09	2009-10	2010-11	POI
Productivity per day	MT	16	24	26	32
Productivity per employee	MT/day	16	24	27	31

**H. Magnitude of Dumping Margin**

65. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive and above de-minimis.

**I. Growth**

66. The Authority notes that the domestic industry has shown positive growth in some of the economic parameters such as production, domestic sales, and productivity in POI as compared to the base year. However, profit, cash profit, ROCE, etc have deteriorated in POI as compared to the base year. The Authority further notes that, the volume of imports from the subject country in absolute terms and market share has increased significantly during the POI.

**J. Causal Link**

67. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

- i. **Imports from Third Countries:** - The Authority notes that Imports of product under consideration from other countries are negligible and therefore could not have caused injury to the domestic industry.
- ii. **Contraction in Demand:** - The Authority notes that there is no contraction in demand as the demand of the subject goods in the country has consistently increased throughout the injury period.
- iii. **Pattern of consumption:** - It is noted that no significant change in the pattern of consumption for the subject goods has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission to that regard.
- iv. **Conditions of competition:-** The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.
- v. **Developments in technology:** - The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have caused injury to the domestic industry.
- vi. **Export performance of the domestic industry:** - The price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

#### **Likelihood of dumping and injury**

#### **Submissions by the domestic industry**

68. Following are the submissions made by the domestic industry:

- i. Domestic Industry submits that the dumping of Paracetamol continued from China even after the imposition of anti dumping duty.
- ii. The Designated Authority has conducted two investigations against China PR concerning dumping of Paracetamol. Both the previous investigations i.e. original investigations as well as sunset review investigation have established existence of significant dumping.
- iii. China is a major exporter of Paracetamol and is exporting the product to many countries. In fact 99% of total imports of the subject goods into India, is by the subject country only. China has attracted anti dumping duties on paracetamol from other jurisdictions as well, such as South Africa, Indonesia and European Union. South Africa in its sunset review investigation, concluded in the year 2011, has continued the imposition of antidumping duties on imports of subject goods from China.
- iv. Imports from the subject country are undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market. There existed a significant



price undercutting in the whole injury period. Even after the existence of the current anti-dumping duty, imports from the subject country are undercutting the domestic prices.

- v. The landed price of imports is substantially below the cost and selling price of the Domestic Industry. Thus, in the event of cessation of current anti-dumping duty and if the domestic industry chooses to sell at the import prices, the Domestic Industry would suffer significant financial losses.
- vi. The exporters and producers from the subject country have continued to export the material at the dumped prices even after the imposition of the anti-dumping duty. There is no reason to consider that revocation of duties in the present case would not result in intensified dumping from China PR.
- vii. It is submitted that producers in China PR maintain huge capacities to produce subject goods as shown in the table given below. In case of revocation of anti-dumping duty, the volume of subject goods' imports is bound to increase further.

SN	Producers In China	Capacity (MT per annum)
1.	Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd	25,000
2.	Jiangsu Guoheng Pharma Chemical Co., Ltd	2,500
3.	Runqi Trading Co., Ltd.	12,000
4.	Shanghai Bailion Chemicals Co., Ltd.	50,000
5.	Changshu Huagang Pharmaceutical Co., Ltd	8,000
6.	Jiangsu World Kindly Pharmaceutical Co., Ltd	10,000
7.	Wenzhou Pharmaceutical Factory	6,000
8.	Zhejiang Kangle Pharmaceutical Co., Ltd	20,000
9.	Anqiu Luan Pharmaceutical Co. Limited	24,000

- viii. Landed value of imports are at a price which is lower than the selling price of Domestic Industry. The Chinese producers would therefore aggressively target Indian market in the event of cessation of duty
- ix. The domestic industry's performance in Dry Cell Battery case, significantly improved since the imposition of duty and was making profits. However, in the instant investigation performance of the domestic industry deteriorated in terms of inventories, market share, profits, return on investments, cash flow and the product under consideration continues to be exported to India at dumping prices from the subject country.

3709 GI/13-10

**Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties**

69. Following are the submissions made by the opposite interested parties:

- i. The petitioners have failed to make a case of likelihood of dumping as they haven't given the details of excessive capacity available with the Chinese Producers.
- ii. The current situation is not a special case where the anti-dumping duty should be extended for another five years as held in the investigation on Dry Cell Batteries.

**Examination by the Authority**

70. The present investigation is a sun set review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, as there are continued dumped imports, the Authority is not required to examine whether revocation of duty is likely to lead to continued dumping of the product. However, considering the fact that the dumping margin in the original as well as the present investigation is significant and that there are favorable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that dumping will intensify if the duty is revoked. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country could maintain a significant presence in the Indian market to the detriment of the domestic industry.

71. The following analysis speaks about the likelihood of intensification of dumping and aggravated injury to the domestic industry in the event of revocation of the duty:

**Level of current and past dumping margin**

72. Considering the dumping margin determined by the Authority in the previous investigations and the dumping margin now assessed, it is quite evident that the exports were continued to be made at dumped prices and is likely to continue with revocation of anti-dumping duties. Volume of imports has significantly increased even after imposition of anti-dumping duties. The volume of imports in the current investigation period is higher than even the original investigation period. Further, the volume of imports is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping

duties, given the significant price undercutting and underselling during the injury period. The level of dumping margin established in the original, first sunset review and in the current investigations as given in table below, is an indicator of likely dumping in the event of revocation of anti-dumping duties:

Investigations	Dumping margin %	Dumping margin Range %
Original	***	40-50
First sunset review	***	20-30
Current sunset review	***	20-30

The level of dumping margin as compared above indicates that the anti-dumping measures as imposed in the past investigations has not deterred the exporters of subject country to dump the subject goods in the Indian market.

#### **Anti-dumping duties imposed by other countries**

73. South Africa in its sunset review investigation, concluded in the year 2011, has continued the imposition of antidumping duties on imports of subject goods from China. South Africa has imposed duties at the rate of 2,573 cents/kg. Considering the high production capacity in China and the Chinese propensity to dump goods in Indian market and increasing demand in India, in the event of revocation of anti-dumping duty on imports of subject goods, there is all likelihood that the dumping of the subject goods in India will be further intensified.

#### **Price attractiveness of Indian market**

74. The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of continuation/intensification of dumping. At the landed price in India, there is significant undercutting both with and without duty. Thus, with the revocation of anti-dumping duties, the Indian prices would be too attractive for the Chinese producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from China.

#### **Huge Production Capacity in China**

75. As claimed by domestic industry, there are at least 9 producers of the subject goods in China holding a combined production capacity of more than 1.5 lakh MT. The Indian production of subject goods is just a miniscule

of the Chinese capacity. In the event of revocation of anti-dumping duty and considering the Chinese export orientation, the producers of China are capable of completely overtaking the Indian manufacturing sector engaged in subject goods

#### **Market share of China PR in the Indian market**

16 The Authority notes that despite the anti-dumping duty in place, the market share has remained significant throughout the injury period including POI.

#### **Magnitude of Injury and injury margin - POI**

17 The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Particulars	Unit	Chinese producer/ exporter
Non injurious price of the domestic industry	Rs/Kg	***
Landed price without ADD	Rs/Kg	157
Injury margin	Rs/Kg	***
Injury margin	%	***
Injury margin % range	Range %	15-25

The Authority notes that the injury margin worked out as above is substantial.

#### **Indian industry's interest and other issues**

18 The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

79. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Further, imposition of anti-dumping duties, would not affect the availability of the product to the consumers.

#### **Post Disclosure Comments**

80. Following are the post disclosure comments made by the producer/ exporter/importers/other interested parties:

- i. Authority should accept the response of Hebei Jiheng, China and determine separate dumping margin for them.
- ii. Information regarding Meghmani, one of the largest producers of the subject goods in India, was not provided by the petitioners.
- iii. As per the annual report of Pan Drugs, During POI of 15 months i.e. they have produced 1115 MT of paracetamol, which the petitioners have not taken in to account.
- iv. The petitioners have misrepresented about the domestic producers in India and the total domestic production of the subject goods. In view of that position, the petitioners lack standing and therefore the investigation needs to be terminated forthwith.

81. Following are the post-disclosure comments made by the domestic industry:

- i. The non injurious price determined is too low.
- ii. The domestic industry is suffering continued injury due to continued dumping of the subject goods from the subject country. Continued dumping, likelihood of significant undercutting, and excessive capacities with Chinese producers and export orientation of these producers, collectively show that if the present anti dumping duty is revoked, the injury to the domestic industry would aggravate.

#### **Examination by the Authority**

82. The post-disclosure comments made by the interested parties are mostly reiterations. However, the comments considered relevant by the Authority are addressed below:

- i. As regards the submission of the domestic industry that the non-injurious price determined is too low, the Authority notes that the NIP has been determined as per the Rules based on verified data and consistent practice of the Authority.
- ii. As regards the submission that separate dumping margin should be determined for M/s Hebei Jiheng, China, the Authority notes that the belated questionnaire response filed by the said Chinese exporter was rejected and therefore the question of determination of separate dumping for them does not arise.
- iii. As regards the submission that information regarding Meghmani, one of the largest producers of the subject goods in India, was not provided by the petitioners, the Authority notes that the said domestic producer has supported the application.
- iv. As regards the submission that M/s Pan Drugs has produced 1115 MT of paracetamol during the POI (15 months) and the petitioners have not taken the said figure in to the total domestic production, the Authority notes that the interested party has taken the production figure as per the annual report of the company procuring from the Registrar of Company (ROC). The information provided therein states "quantity of highest contributing product or service", classified under ITC 0030049005, which is found to be pertaining to "Paracetamol tablets", which is not the subject goods in the present investigation. The subject goods in the present investigation is Paracetamol, an organic chemical in the bulk form.
- v. As regards the submission that the petitioners have misrepresented about the domestic producers and the total domestic production of the subject goods in India, the Authority notes that the present sunset review investigation was initiated on the basis of an application filed by M/s Sri Krishna Pharmaceutical Ltd and M/s Bharat Chemicals. Post initiation, the Authority had provided a copy of the initiation notification to the other domestic producers of the subject goods as per the information provided by the applicants namely Para Products, Sara Exports Ltd, PAN Drugs Ltd, Paracetamol Health Care Ltd, Farmson Analgesics, Alpha Drugs Ltd and Granules India Ltd. While M/s Sara Exports, M/s Para Products, M/s Farmson Analgesics and M/s Meghmani Unichem have supported the application, the others neither supported nor opposed the application. The issue of standing has already been adequately examined and addressed by the Authority in the relevant paras of this finding and the Authority has already held that the applicants in the present sunset review investigation namely M/s Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd and M/s Bharat Chemicals and supported by M/s Sara Exports, M/s Para Products, M/s Farmson

Analgesics and M/s Meghmani Unichem account for a major proportion in the Indian production of the subject goods and constitute domestic industry satisfying the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

### **CONCLUSIONS**

83. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. Import of the subject goods from China PR has remained at significant level throughout the injury period and continues to command a significant share during the POI.
- ii. There has been continued dumping of the subject goods from China PR and the dumping is likely to continue and increase if the anti-dumping duty is allowed to cease.
- iii. Price undercutting and price underselling has been significantly positive both with and without anti-dumping duty.
- iv. The performance of the domestic industry in terms of profits, return on investments, cash profit, etc. has deteriorated in POI, whereas the same should have normally improved after imposition of anti-dumping duties.
- v. Although the domestic industry has shown some positive growth in some of the economic parameters such as production, domestic sales, and productivity during the POI, the improvement in these economic parameters is largely on account of the anti-dumping measures in force.
- vi. Despite the anti-dumping measures in force, the subject goods are entering the Indian market at dumped prices and both the dumping margin as well as the injury margin has remained significant, resulting in continued injury to domestic industry.
- vii. Volume of import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, has remained significant throughout the injury period and substantially increased during the POI despite the anti-dumping duty in force. Given the significant price undercutting and price under selling and considering the capacity in China and demand in India, the volume

of dumped import is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

- viii. Considering the magnitude of dumping margin in the earlier investigation and the dumping margin determined by the Authority in the present investigation, it is evident that the exports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, were continued to be made at dumped prices injuring the domestic industry despite the anti-dumping duty in force. Despite the anti-dumping measures, dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country has continued unabated causing injury to the domestic industry. Should the present anti-dumping duties be revoked, dumping of the subject goods may in all likelihood intensify, causing further injury to the domestic industry.

#### A. Recommendations

84. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measure is required to be revised and extended in respect of imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, as specified in the duty table below. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 9 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, by the Central Government.

85. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry, as specified in the duty table below.

**Duty Table**

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	29222933	Paracetamol	All grades	China PR	China PR	Any	Any	787	MT	US \$
2.	-Do-	-Do-	-Do-	China PR	Any country other	Any	Any	787	MT	US \$



					than China PR					
3.	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	787	MT	US \$

### **B. Further Procedures**

86. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs Authority under the Customs Act, 1962 and all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

87. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

J.S. DEEPAK, Designated Authority